स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–11, कार्तिक–मार्गशीर्ष– 2069, नवम्बर 2012

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आन्दोलन–4

स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत अक्टूबर माह में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिए जाने के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में .. .

कवर पेज

अनुक्रम

आन्दोलन

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोध में पदयात्रा /4

पड़ताल

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश : अतार्किक दावे
– मुरलीधर राव /6

कृषि : हर भूखे को होगी रोटी
– डॉ. अनुराग शर्मा /10

बीज : जीएम बीजों का घातक परीक्षण
– भारत डोगरा /14

सामयिकी : चक्रव्यूह में फंसे किसान
– देविन्दर शर्मा /16

मुद्दा : महंगाई की मुश्किल कैसे हो कम!!
– जयंतीलाल भण्डारी /18

सवाल : नकद सब्सिडी पर सवाल
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /21

दृष्टिकोण : रिवर्ज बैंक की मृगमरीचिका
– डॉ. अश्विनी महाजन /23

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार
– निरंकार सिंह /25

भ्रष्ट–तंत्र : आम आदमी से दूर भागती सरकार
– बलवीर पुंज /27

समस्या : तंत्र के चक्रव्यूह में नक्सलवाद
– उमेश चतुर्वेदी /29

लेख : सर्वसमावेशी स्वदेशी
– विद्यानंद आचार्य /31

पशुधन : गो दूध के लाभ
– उमेश प्रसाद सिंह /33

फिजूलखर्ची : क्या पेड़ में पैसे उगते हैं
– गिरिश अवस्थी /33

पाठकनामा/2, रपट/34

पाठकनामा

गैर तो गैर थे अपने भी गैर हुए

हमारा देश भारत दुनिया में सबसे महान देश है। इसमें बड़े–बड़े ऋषि मुनियों, देवी–देवताओं ने जन्म लिया। कुदरत ने मनुष्य जीव–जन्तुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा दी। मनुष्य उपयोगी फल–फूल, जड़ी–बूटियां, हरियाली प्रदान की साथ ही समय चार ऋतुएं दी। उपरोक्त सभी मनुष्य उपयोगी सौगात अन्य देशों को नहीं दी। हमें गर्व होना चाहिए की हमने भारत जैसे महान देश में जन्म लिया। इसलिए दूसरे देशों ने हमारे देश को 'सोने की चिड़िया' का नाम दिया।

हमारे देश के कुछ गद्दारों ने विदेशीयों से हाथ मिला कर अपना हित समझकर विदेशीयों को हमारे राजफाश किए। पहले हमारे देश में मुगल आए, उन्होंने हमारे देश को दोनों हाथों से लूटा। बहादुरशाह जाफर के कार्यकाल में गोरे अंग्रेज व्यापार करने के लिए उनके दरबार में घड़ियाली आँसू निकाल कर उनसे व्यापार करने की इजाजत माँगी और बहादुरशाह जाफर ने इजाजत दे दी। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनायी। अपने देश से वे सामानों के साथ–साथ सैनिक, गोला–बारूद, बन्दूकें, तोपों का सामान भी मंगवाते रहे। फूट डालो का मंत्र अपनाकर उन्होंने राजाओं को एक–दूसरे से लड़वाते रहे। धीरे–धीरे अंग्रेज भारत के मालिक बन बैठे। फिर देश गुलामी के दो राहे पर आ गया। अंग्रेजों ने भारत को दोनों हाथों से लूटा और सोना–चाँदी अपने देश में ले गए। ये कार्य रानी विकटोरिया के कहने पर होता रहा जिसके कारण भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ गई। अंग्रेजों ने भारत को लूटा मगर देश में विकास भी किया। लोहे के पुल बनाए, नहरे बनाई, सड़कें बनाई साथ ही कभी–कभी जनता को इंसाफ भी दिया। जनता जागी और देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटा और काफी संघर्ष के बाद भारत देश आजाद हुआ। अब गोरे अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई। काले अंग्रेजों ने भारत में जन्म लिया, यही का अन्न–जल खा–पीकर बड़े हुए। विकास के नाम पर देश की जनता को भूखमरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी और महंगाई दी। आम जनता के विकास की जो भी योजनाएँ बनाई गई उसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं ने दोनों हाथों से लूटकर भारत के विकास का पैसा विदेशों के बैंकों में जमा कर हिन्दुस्तान की जनता को विदेशी कर्ज के बोझ में दबा दिया। आज जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वह भी विदेशी कर्ज में है। ये भ्रष्टचारी अधिकारी और नेता 'भारत माता की जय' का नारा तो लगाते है परंतु भारत माता को लूटकर विदेशों में पैसा जमा कराते हैं। इन्होंने जनता के पैसों को विदेशी बैंकों में क्यों जमा किया? काले अंग्रेज होश में आओ, अपनी संस्कृति अपने देश को पहचानों, जीवन पूरा होने के साथ कुछ भी साथ नहीं जाता केवल कर्म साथ जाता है। अतः भगवान की बेजुबान लाठी से डरो उसका कहर किस पर फूट पड़े कोई नहीं जानता।

– भुवनेश कुमार त्यागी, 510 मल्लूपूरा साकेत मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

केन्द्र सरकार वित्तीय मोर्चे पर और स्वच्छ छवि वाला प्रशासन देने में असफल रही। उसके पास 2जी और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले पर बोलने को एक शब्द भी नहीं है।

– अरुण जेटली

पेट्रोलियम मंत्रालय जिसके पास भी रहेगा, वह हताश ही रहेगा। भारत जरूरत का 75 फीसद तेल आयात करता है। इसके बावजूद भगवान भी नहीं बता सकते कि तेल की कीमतें कौन बढ़ा रहा है।

– एस जयपाल रेड्डी

भ्रष्टाचारियों को सजा देने के मामले में सरकारी एजेंसियां फिसड्डी साबित हुई हैं। इस मामले में हमारा रिकार्ड एकदम दयनीय है।

– सीवीसी आर श्रीकुमार

दिल्ली में धुंध की गहराती चादर से चिंतित हैं। हर दिन शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर बात हो रही है।

– अल्तमश कबीर, मुख्य न्यायधीश

सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अनुमति देने से खुदरा व्यापार से जुड़े भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

– गोविन्दाचार्य

आठ साल में प्रधानमंत्री घोटालों के चौक्के–छक्के लगा रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।

– पी मुरलीधर राव

संपादकीय

सोचे भारत सरकार

अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर ओबामा चुन लिए गए है। वहां के नागरिकों को यह लग रहा है कि ओबामा ही अमरीकी अर्थव्यवस्था को संभाले रख सकते है। चार वर्ष पहले वहां की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपने कर्जे को संभाल नहीं पा रहे थे और यहां तक कि कर्ज न चुका पाने के कारण अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। बेरोजगारी चरम पर थी और अमरीका के बड़े –बड़े बैंक तक डूबने लगे थे। ऐसा लगा रहा है कि इस समय अमरीकी अर्थव्यवस्था स्थिरता की ओर है। वहां समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बिखरने का खतरा फिलहाल टल गया है। लोग अब ओबामा को मैन ऑफ एक्शन यानी फैसले लेने वाले व्यक्तित्व का मालिक बताने लगे हैं। आखिर ओबामा ने ऐसा किया क्या? अगर एक वाक्य में कहें तो ओबामा ने अमरीकी हितों को साधने के लिए अपनी कूटनीतिक सूझ–बूझ का पूरा परिचय दिया। वहां के एक आम आदमी को अमरीका के सुपरपावर होने का फिर से अहसास कराया। चाहे वह ओसामा बिन लादेन को मारने का फैसला हो या फिर भारत से संबंध खराब होने के जोखिम को मोलकर भी आउटसोर्सिंग सीमित करने का मामला। ओबामा ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अपने कूटनीतिक व्यवहार को नरम और आर्थिक फैसलों को आक्रामक बनाए रखा। बाकी दुनिया के देशों से आपसी संबंध बनाए रखने की पूरी कीमत ओबामा ने वसूल की। भारत का ही उदाहरण लें। जब राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो उनके पास एक ही एजेंडा था कि यहां के शीर्ष नेताओं को इस बात के लिए राजी करवाना कि वे यहां खुदरा व्यापार में बहुब्रांड वाली कंपनियों के बड़े स्टोर खोलने की आजादी दें। यानी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को मंजूरी दें। पूरे देश के सामने साक्ष्य है कि भारत ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा व्यापार के क्षेत्र में आने की मजूंरी दे दी है।

भारत सरकार ने ओबामा के दबाव में खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने की छूट दे दी, हालांकि देश की अधिकतर राजनैतिक पार्टियां इसके लिए राजी नहीं है, सरकार की स्थिरता भी दांव पर लगी है। जबकि अमरीका पहले से ज्यादा सशक्त होता जा रहा और भारत जो दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने का स्वपन देख रहा था सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, गिरती आर्थिक संवर्द्धन की दर, बढ़ते राजकोषीय घाटे और बढ़ते भुगतान संकट के चलते रुपए की अवमूल्यन की त्रासदी से गुजर रहा है। 2002 तक पूरी दुनिया यह मानती रही कि भारत वर्ष 2020 तक दुनिया का दूसरा या तीसरा आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अमरीका और यूरोप अपनी ताकत खोते जाएंगे और चीन तथा भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता मजबूत करते जाएंगे। यह भी माना जाने लगा था कि वर्ष 2050 तक अमरीका और यूरोप बूढ़े हो जाएंगे और भारत ही पूरी दुनिया का काम–काज संभालेगा, क्योंकि यहां की 60 फीसदी जनसंख्या युवा है। भारत की अर्थव्यवस्था 8 फीसदी की दर से बढ़ेगी और अमरीका तथा यूरोप नकारात्मक वृद्धि दर की तरफ चले जाएंगे।

अपने देश को कमजोरी से उबारते हुए जिस प्रकार से ओबामा ने अपनी देश में अपनी साख बनाई, उसी समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली भारत सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया और भ्रष्टाचार में डूबते हुए दुनिया में भारत की साख पर बटा लगाया। हमारे नीति–निर्माताओं को समझना होगा कि देश की प्रगति, स्थिरता और आर्थिक फैसलों में पारदर्शिता के माध्यम से ही देश अपनी साख बचा सकेगा।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में
स्वदेशी जागरण मंच की पदयात्रा

वालमार्ट को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से चाहे जितना ऋण चाहिए उसके बैंक उसे दे देते हैं। जबकि भारत के दुकानदार अपना व्यापार 99.99 प्रतिशत अपनी ही पूंजी अथवा मित्रों से ऋण लेकर कर रहे हैं। यूपीए सरकार बताएं कि देश के कुल खुदरा व्यापार में सरकारी बैंकों ने दुकानदारों को कितना ऋण दे रखा है।

– मुरलीधर राव

स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत अक्टूबर माह में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिए जाने के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में अशोक नगर फाटक से प्रारंभ होकर मंडौली,, लोनी रोड़, कबूल नगर, हनुमान रोड़ के प्रमुख बाजारों से होती हुई वेलकम कालोनी पर समाप्त हुई।

पदयात्रा में स्वदेशी आंदोलन के प्रखर नेता श्री मुरलीधर राव, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन मंत्री श्री अभय महाजन ने भाग लिया।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि सरकार देश की जनता के साथ धोखा किया है। वर्तमान राष्ट्रपति जब 2011 में वित्तमंत्री थे तो उन्होंने संसद में सरकार की ओर से वचन दिया था कि इस मुद्दे पर देश के सभी दलों से सर्वसहमति बनाने के उपरांत इस निर्णय को लागू किया जाएगा। किंतु सरकार ने बिना किसी से चर्चा किए हुए इसे लागू करके अपना वचन तोड़ दिया है।

वालमार्ट को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की जनता को अंधेरे में रखकर कपटपूर्ण तरीके से किया गया है। अतः वालमार्ट की संपत्तियों एवं उसके निवेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की जनता की नहीं है।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा अपितु किसानों को भी भारी नुकसान होगा।

श्री राव ने कहा कि जहां एक ओर तो वालमार्ट को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से चाहे जितना ऋण चाहिए उसके बैंक उसे दे देते हैं। जबकि भारत के दुकानदार अपना व्यापार 99.99 प्रतिशत अपनी ही पूंजी अथवा मित्रों से ऋण लेकर कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार बताएं कि देश के कुल खुदरा व्यापार में सरकारी बैंकों ने दुकानदारों को कितना ऋण दे रखा है।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा अपितु किसानों को भी भारी नुकसान होगा। देश के बीज पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है व घरेलू बीज समाप्त होते जा रहे हैं।

श्री अभय महाजन ने एफडीआई को खतरा बताते हुए कहा कि देश के खाद्य वितरण तंत्र को विदेशी कंपनियों के हवाले

सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अनुमति देने से खुदरा व्यापार से जुड़े भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
– गोविन्दाचार्य

करना देश की सुरक्षा के लिए भारी खतरा उत्पन्न करेगा।

मंच के राष्ट्रीय परिषद् सदस्य श्री जितेन्द्र महाजन ने कहा कि एफडीआई से छोटे और लघु उद्योगों की कमर ही टूट जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप भयानक रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी।

पदयात्रा में मंच के दिल्ली प्रांत के सह–संयोजक श्री सुशील पांचाल, विभाग संयोजक श्री मनोज गुप्ता, सह–विभाग संयोजक श्री संदीप चौधरी व श्री लोकेश शर्मा, व्यापार प्रकोष्ठ प्रमुख श्री पंकज शर्मा सहित हजारों कार्यकर्ताओं एवं व्यापारियों ने भाग लिया। अनेक स्थानों पर पदयात्रा का व्यापारी नेताओं के द्वारा भारी स्वागत किया गया।

बिजली के बढ़े दामों पर भी मंच का आंदोलन

बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से रैली निकाल कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया।

मंच के दिल्ली प्रांत के संयोजक जितेन्द्र महाजन के नेतृत्व में निकाली गई विरोध रैली लोनी रोड, गोल चक्कर से शुरू होकर मीतनगर, अमर कालोनी व गोकलपुरी में समाप्त हुई।

रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता डॉ. हर्षवर्धन व विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बिजली का निजीकरण कर बिजली कंपनियों के हाथों बिक चुकी है।

उन्होंने कहा कि डीआईआरसी ने जनसुनवाई के दौरान बिजली की बढ़ी दरों को कम करने को कहा था मगर वह सब केवल कागजी घोषणा ही रह गई। न तो बिजली की बढ़े दर घटाए गए और न ही बिजली के स्लैब को बदला गया।

इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर भारत के प्रमुख प्रदीप शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से खुदरा व्यापार से जुड़े भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

भ्रष्ट–घोटालों सरकार और एडीआई के विरोध में रैली

कांग्रेस की भ्रष्ट व घोटालों की दिल्ली सरकार व यूपीए समर्थित केंद्र सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को अनुमति देने तथा बिजली व पानी के बिलों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत द्वारा एक जन–जागरण रैली निकाली गई व रैली के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया।

विशाल रैली का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत के संयोजक जितेन्द्र महाजन ने किया।

इस अवसर पर गोविन्दाचार्य व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कश्मीरी लाल उपस्थित थे। विशाल जनजारगण रैली मैन विजय पार्क रोड से शुरू होकर नूरे इलाही रोड, घोंडा चौक, मैन रोड, मौजपुर, कर्दमपुरी होते हुए दुर्गापुरी चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मंच के कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता तथा व्यापारी संगठनों ने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व इसको वापस लेने की मांग की।

श्री गोविन्दाचार्य व मंच के संगठन महामंत्री कश्मीरी लाल ने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अनुमति देने से खुदरा व्यापार से जुड़े भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

इस अवसर पर निगम स्थायी समिति के सदस्य संजय कौशिक, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रणजीत कश्यप, मंडल अध्यक्ष मुकेश अरोड़ा, दीपक जैन, स्वदेशी जागरण मंच के उमेश ठाकुर सहित हजारों की संख्या में आए मंच के कार्यकर्ताओं व मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी व आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी व स्थानीय जनता भी उपस्थित थे। ❑

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश : अतार्किक दावे

वालमार्ट भारत में अपना स्टोर खोलना चाहती है उसकी सालाना आय 422 बिलियन डॉलर है। हालांकि वह सिर्फ 21 लाख लोगों को रोजगार देती है। भारत में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा टर्नओवर वाली ये कंपनी भारत के खुदरा में रोजगार का 5 प्रतिशत से भी कम रोजगार के अवसर दे रही है। रोजगार पर ये दाव फर्जी है। वालमार्ट और टेस्को जो कहीं नहीं कर सके, वो यहां कैसे करेंगे. . .

■ मुरलीधर राव

खुदरा बाजार में विदेशी निवेश की अनुमति के अपनी सरकार के फैसले के पक्ष में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई तर्क दिए। उन्होंने इसे वैधता प्रदान करने की कोशिश की। इस विश्लेषण में इस मसले को सही तरीके से देखने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए हैं :–

(1) संगठित खुदरा बाजार के विकास से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

(2) बुनियादी ढांचा खड़ा होने से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी।

(3) किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा।

(4) उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उन्हें चीजें सस्ते दामों पर मिलेंगे और अंततः महंगाई पर लगाम लगेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ हैं। इसलिए राज्यों को ये फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आने देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य को इसलिए नहीं रोक सकता कि वो अपने किसानों, युवाओं और उपभोक्ताओं को अच्छी जिंदगी दे। सरकार के तर्कों की बखिया उधेड़ने के लिए अंतिम बयान को सबसे पहले लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस बयान के जरिए उन राज्यों को मनाने की कोशिश की गई है, जो खुदरा में विदेशी निवेश के खिलाफ हैं।

यह सबको पता है कि कांग्रेस शासित केरल ने भी खुले रूप से खुदरा में विदेशी पूँजी का विरोध किया है।

दलील दोषपूर्ण है क्योंकि राज्यों के हाथ बंधे हैं

सरकार का कहना है कि उसने सिर्फ नीति बनाई है और इसका फैसला राज्यों को करना है कि वे अपने क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस देंगी या नहीं। यह उस 'नेशनल ट्रीटमेंट' के एकदम उलट है जो सरकार ने निवेश करने वाले देशों को दिए हैं। जुलाई में सरकार ने द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एण्ड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट किया है। इसके जरिए निवेशकों के निवेश को सुरक्षा दी जाती है। ये समझौते 82 देशों के साथ हुए हैं। इनमें से 72 देशों के साथ य समझौते लागू हो गए हैं। बाकी बचे समझोते लागू होने की प्रक्रिया में है। इससे संबंधित जानकारी वित्त मंत्रालय की वेवसाइट पर है।

'नेशनल ट्रीटमेंट' से जुड़ा प्रावधान है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। वास्तव में मतलब है कि अगर नीलगिरी चेन्नई में, बिग बाजार कोलकाता में या ईजी डे उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्षेत्र बनाता है तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकार वालमार्ट या टेस्को को स्टोर खोलने से नहीं रोक सकते। अगर शॉप एण्ड इस्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस देने से इनकार किया जाता है तो इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है।

वीआईपीए समझौते के तहत सभी राज्यों समेत पूरा देश इसे लागू करने के लिए बाध्य है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में प्रधानमंत्री से अच्छा कौन जानता है। लगता है कि सरकार खुदरा में विदेशी निवेश लाने को लेकर जल्दी में थी और इसलिए इस तरह की दोषपूर्ण दलीलें दे रही है।

नौकरी

रोजगार : रिटेल में एफडीआई से रोजगार के अवसर खत्म होंगे

प्रधानमंत्री कहते हैं कि संगठित खुदरा के विकास से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जो इस प्रकार के संकट प्रबंधक थे, दलील दे रहे हैं कि इस प्रस्तावित नीति के अगले तीन साल में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार की दलील है कि खुदरा क्षेत्र में भारी निवेश होने से एग्री, प्रोसेसिंग, सोर्टिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और फ्रंट–इंड रिटेल में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह कोई नया तर्क नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया लम्बे समय से इसकी वकालत कर रहे हैं। एनडीए शासन काल के दौरान वे योजना आयोग में सदस्य थे और हर साल एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कार्यसमूह के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एफडीआई का समर्थन किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि खुदरा में एफडीआई से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उस वक्त तत्कालीन सरकार ने उनकी रिपोर्ट खारिज कर दी। वहीं एस.पी. गुप्ता की अगुवाई में नई समिति बनाई गई। एस.पी. गुप्ता ने हर साल एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई रास्ते सुझाए जिनमें श्रम प्रधान तकनीकों को बढ़ावा देना और स्वरोजगार शामिल था।

कोई नहीं समझ रहा सरकार की दलील

सरकार के संकट प्रबंधक अपनी बातों को समझाने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन कोई भी इस दलील को स्वीकार नहीं कर रहा। सरकार के तर्क बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन से उधार लिया गया है। भारत में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 11 दुकानें हैं। दुनिया में ये अनुपात सबसे अधिक है। औद्योगिक नीति और संवर्धन बोर्ड ने जो पेपर तैयार किया उसमें खुदरा में एफडीआई का संकेत देते हुए जाना गया कि देश में 120 लाख छोटी–बड़ी दुकानें हैं। इससे 3.5 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। इसके अलावा 1.5 करोड़ लोग थोक, ट्रांसपोर्ट और अन्य गतिविधियों में लगे हैं। यह अहम है कि 95 प्रतिशत छोटी दुकानों को चलाने वाले अपना स्वरोजगार कर रहे हैं।

वालमार्ट ने शिकागो के पॉप ऑस्टिन में 2006 में दुकान खोली। 2008 तक 82 दुकानें बंद हो गई जबकि इसके आने से पहले यहां 306 छोटी दुकानें थीं। द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट क्वाटर्ली के अध्ययन के मुताबिक वालमार्ट के आसपास दुकानें बंद होने की दर 35–60 प्रतिशत है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि छोटा खुदरा व्यापार अमेरिका और यूरोप में खत्म हो गया है। छोटे दुकानदरों के हितों की रक्षा के लिए राज्यों और कई यूरोपीय देशों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दक्षिण–पूर्व एशिया के भी कई देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ऐसी ही पाबंदियां लगाई है। खुदरा कारोबार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने की शुरुआत 1960 में हुई। इन कंपनियों ने विकसित और विकासशील देशों में खुदरा कारोबार के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। अमेरिका का 80 प्रतिशत खुदरा कारोबार इन्हीं कंपनियों के नाम है। ऐसी ही स्थितियां इंग्लैण्ड और पश्चिम यूरोप के दूसरे देशों में है। यहाँ खुदरा बाजार का 50 प्रतिशत हिस्सा इनके पास है। ब्राजील और अर्जेंटीना में भी 40 प्रतिशत खुदरा बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है। यहां तक कि चीन में भी इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। 1960 तक इन कंपनियों क कहीं नामोनिशान नहीं था लेकिन इसके बाद इन्होंने कई देशों में छोटे कारोबारियों पर असर डाला। वर्तमान में 20 बड़ी कंपनियां हैं। यह स्पष्ट है कि संगठित खुदरा कारोबारियों ने इस क्षेत्र में अपना रोजगार कर रहे लोगों को बाहर धकेल दिया है। यहां तक कि आईसीआरआईईआर ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि दो प्रतिशत दुकानें हर साल बंद होंगे, अगर खुदरा में एफडीआई की अनुमति दी गई तो।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से लगता है कि छोटी दुकानें ज्यादा तेज गति से बंद होंगे। वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शुरुआत में बहुत सस्ते में अपने उत्पाद बेचती है। फिलहाल सरकर कह रही है कि देश में 53 बड़े शहरों में ही ऐसी दुकानें खुलेंगी। इससे इन शहरों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर छिन जाएंगे क्योंकि छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ छोटी दुकानें बंद होने से ही रोजगार नहीं जाएगा। देश के विनिर्माण आयोग की रफ्तार घटने से भी नौकरियां खत्म होंगी। ये कंपनियां हमेशा सस्ते उत्पाद खरीदने की कोशिश करती

है। अमेरिका का अनुभव बताता है कि वालमार्ट के स्टोर में बिकने वाले अधिकतर उत्पाद चीन से आते हैं। यह आम है कि चीन के उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार वालमार्ट है। आज अमरीका का नामी जूता उद्योग पूरी तरह बंद है क्योंकि वहां के जूते खुदरा कंपनियां नहीं खरीद रही हैं। अमेरिका में एक समय में विनिर्माण क्षेत्र में 195 लाख लोग लगे थे। 2011 में ये संख्या घटकर 118 रह गई। मतलब पिछले 32 सालों में 77 लाख रोजगार के अवसर घटे हैं। पश्चिमी यूरोप में भी स्थितियां ज्यादा अलग नहीं है।

अतः ये पूरी तरह प्रमाणित है कि खुदरा में एफडीआई आने से विदेशों के उत्पाद भारी संख्या में देश में आएंगे और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखने को मिलेगी। खुदरा में एफडीआई की नीति की घोषणा करते वक्त सरकार ने असफल रूप से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। ये कहा कि खुदरा में एफडीआई को इस शर्त पर अनुमति दी गई है कि 30 प्रतिशत उत्पाद छोटे और मझोले उद्योगों से खरीदने होंगे। बाद में सरकर ने स्पष्ट किया कि ये नियम देश के भीतर की छोटी कंपनियों के लिए नहीं है। ये शर्त विश्व व्यापार संगठन की समझौते के उलट भी है। इसलिए खुदरा में एफडीआई आने से उपभोक्ता सामान बनाने वाली बहुत सी छोटी इकाईयां बंद हो जाएंगी। विनिर्माण के अलावा परिवहन और थोक खुदरा पर भी असर पड़ेगा और यहां भी रोजगार के अवसर खत्म होंगे।

जो कंपनी (वालमार्ट) भारत में अपना स्टोर खोलना चाहती है उसकी सालाना आय 422 बिलियन डॉलर है। हालांकि वह सिर्फ 21 लाख लोगों को रोजगार देती है। भारत में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा टर्नओवर वाली ये कंपनी भारत के खुदरा में रोजगार का 5 प्रतिशत से भी कम रोजगार के अवसर दे रही है। रोजगार पर ये दाव फर्जी है। वालमार्ट और टेस्को जो कहीं नहीं कर सके, वो यहां कैसे करेंगे। सवाल उठता है कि वाणिज्य मंत्री को एक करोड़ रोजगार वाला आंकड़ा कहां से मिला। यूपीए ये प्रचारित कर रही है कि वालमार्ट जैसी कंपनियां छोटे कारोबारियों और किसानों की हितैषी हैं। वो गारंटी दे

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि छोटा खुदरा व्यापार अमेरिका और यूरोप में खत्म हो गया है। छोटे दुकानदरों के हितों की रक्षा के लिए राज्यों और कई यूरोपीय देशों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दक्षिण–पूर्व एशिया के भी कई देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ऐसी ही पाबंदियां लगाई है। खुदरा कारोबार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने की शुरुआत 1960 में हुई।

रही है कि ये कंपनियां यहां लाखों लोगों को रोजगार देंगी। लेकिन अमेरिका में सबूत इसके उलट है। अटलांटीसिटी के मुताबिक वालमार्ट ने शिकागो के पॉप ऑस्टिन में 2006 में दुकान खोली। 2008 तक 82 दुकानें बंद हो गई जबकि इसके आने से पहले यहां 306 छोटी दुकानें थीं। द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट क्वाटर्ली के अध्ययन के मुताबिक वालमार्ट के आसपास दुकानें बंद होने की दर 35–60 प्रतिशत है। वालमार्ट ने अपने स्टोर के हर एक मील पर 20 प्रतिशत खुदरा दुकानों को बंद करा दिया। वहीं होम फर्निशिंग में ये आंकड़ा 15 प्रतिशत है। हार्डवेयर में यह 18 प्रतिशत तो खिलौने की दुकानों में 25 प्रतिशत। अमेरिका में हुए अध्ययन यूपीए के झूठ से पर्दा उठता है कि इससे छोटे दुकानदारों पर कोई खतरा नहीं है। वहीं रोजगार के अवसर पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वालमार्ट स्थानीय स्तर पर तीन नौकरियों को खत्म कर दो पैदा करता है।

केन्द्र में युवा विरोध

इस बहस में देश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा दूर रहा है। देश के 30 करोड़ लोग 16 से 29 आयु वर्ग के हैं। आबादी का एक तिहाई 12 साल से अधिक है। लगभग 10 करोड़ लोग 16 से 29 आयु वर्ग के हैं। मान लिया जाए कि इनमें से चार में सिर्फ एक ही रोजगार चाहेगा तो भी अगले पांच साल में 2.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 2009–10 के सर्वे के मुताबिक पिछले दो साल में रोजगार पैदा करने के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकार्ड बहुत खराब है। यह अविश्वसनीय है कि रोजगार के मुख्य स्रोत खुदरा कारोबार को विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना का विकास और खाद्य सुरक्षा का मिथक

इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास होगा, खासकर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज। सरकार की दलील है कि स्टोरेज सुविधा नहीं होने से कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यह कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में कम निवेश से 50 प्रतिशत सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इसका एकमात्र हल रिटेल में एफडीआई है। सरकार तर्क देती है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां गोदाम और कोल्ड स्टोरेज पर

भारी निवेश करेंगी। अगर हम वास्तविकता से देखें तो सरकार ने एक दशक पहले ही गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में एफडीआई की अनुमति दे दी थी। हालांकि इस क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित नहीं किया जा सका।

इसमें दो राय नहीं कि किसानों के हित के लिए स्टोरेज सुविधा जरूरी है। यह भी सही है कि ये सुविधा नहीं होने से कृषि उत्पाद बर्बाद होते हैं। हालांकि बुनियादी सवाल ये है कि स्टोरेज सुविधा के लिए किस पर जिम्मेदारी है? हम समझते हैं कि देश की 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। स्टोरेज कृषि की बड़ी जरूरत है। आजादी के 64 साल बाद भी सरकार अब तक ये सुविधाएं नहीं दे पाई हैं।

एफडीआई पर फैसला लेने की प्रक्रिया में सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन बोर्ड ने अपने बयान में 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन का हवाला दिया। इसमें खुदरा में एफडीआई को जरूरी बताते हुए कहा गया है कि इससे घरेलू आपूर्त्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इसमें कहा गया कि एफडीआई से घरेलू आपूतिकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक पहुंच होगी।

आधारभूत संरचना सरकार की जिम्मेदारी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने को सरकार कृषि उत्पादों के लिए स्टोरेज सुविधा की कमी से जोड़ती है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये सुविधा दे या फिर निजी क्षेत्र को सब्सिडी देकर इस काम के लिए राजी करे। पिछले 65 साल में सरकार बुरी तरह इस क्षेत्र में विफल रही है। सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो छोटे दुकानदारों को इसकी सजा दे।

सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि इसके लिए 7,687 करोड़ के निवेश की जरूरत है, इसलिए विदेशी निवेश चाहिए ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आधारभूत ढांचा खड़ा कर सके। यह दलील गलत है। इस देश में जहां का सालाना बजट 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, वहां 7,687 करोड़ के छोटे से निवेश के लिए हम छोटे दुकानदारों को सूली पर नहीं चढ़ा सकते। वहीं ये कंपनियां सिर्फ अपनी आपूर्त्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए ही ये सुविधाएं खड़ी करेंगी। हम ये आशा नहीं कर सकते कि इन कंपनियों के कोल्ड स्टोरेज में गरीब किसान का आलू रहेगा और उसे मुसीबतों से बचाया जा सकेगा।

वास्तव में बड़ी खुदरा कंपनियां खाद्य पदार्थों की बर्बादी करती है

अगर हम सोचते हैं कि ये कंपनियां खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकती है तो हम गलत है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देश और दूसरे विकसित देश इस मामले में भारत और दूसरे एशियाई देशों से काफी आगे है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में प्रति व्यक्ति 280 किलो, उत्तर अमेरिका में 295 किलो जबकि दक्षिण और पूर्वी एशिया में सिर्फ 125 किलो खाने की बर्बादी होती है। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि जहां खाद्य बर्बादी अधिक है, वहीं बहुराष्ट्रीय संगठित खुदरा व्यापार ज्यादा है। इस दुविधा का जवाब संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन देता है। एफएओ के मुताबिक खाद्य बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कंपनियां गुणवत्ता को लेकर बड़े मानक लागू करती है और कृषि उत्पाद के एक बड़े हिस्से को खारिज कर देती है। जो उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा कभी खेतों से आगे नहीं जा पाता। खारिज किए गए उत्पाद जानवरों के भोजन में काम आते हैं लेकिन इसमें जो मनुष्य के उपयोग के लिए था, उसकी मात्रा घट जाती है।

एफएओ के मुताबिक बड़ी मात्रा में उत्पादों को रखने से औद्योगिक देशों में खाद्य बर्बादी ज्यादा है। रिटेल स्टोर में एक उत्पाद के कई प्रकार होते हैं। उपभोक्ता भी चाहता है कि हर वैरायटी मौजूद रहे। इससे ये आशंका रहती है कि कोई उत्पाद की समय सीमा बिकने से पहले ही खत्म हो जाए और वह बर्बाद हो जाए। खरीददारी के समय ग्राहक चाहते हैं कि दराज पूरी तरह भरे रहें। यह बिक्री आंकड़ों के लिए ठीक है लेकिन लगातार आपूर्त्ति होने से उपभोक्ता की नजर समय सीमा पर नहीं जा पाती है। एफएओ के मुताबिक किसानों द्वारा अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को या दुकानों में बेचना खाद्य बर्बादी को रोकने का अहम औजार हो सकता है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाना न तो किसानों और न ही लोगों के फायदे में है। किसानों को कड़े गुणवत्ता मानकों की वजह से अपने उत्पाद से हाथ धोना पड़ेगा। भारत जैसे देश में सब्जी की छोटी दुकानें खाद्य सुरक्षा में बड़े मददगार हैं। इस लिहाज से गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाना अहम है लेकिन इनका निर्माण सरकार गांवों के पास करे और शायद किसी निजी कंपनियों की मदद लें। मेगा स्टोर या बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाद्य बर्बादी का जवाब नहीं हो सकते। अगर एफसीआई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वालमार्ट के आगे हथियार डाल दें। हमें खुद बुनियादी संरचना खड़ी कर अपने लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा करनी होगी।

(शेष दिसम्बर माह अंक में...)

भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की एकल गेंहू उत्पादन की तुलना में 170 फीसदी अधिक पैदावार लेने की तकनीक

हर भूखे को होगी रोटी

प्रो. सुशील कुमार ने कहा कि अभी तक विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों (ठंड़े क्षेत्र) में दो तरह के गेहूं उगाए जाते हैं। कुछ बर्फीले इलाकों में शरद–शीत–बसंत–ग्रीष्म में विंटर व्हीट यानी शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है, जब कि अन्य समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्प्रिंगव्हीट यानी बसंतकालीन फसल ली जाती है। हमारे देश में अर्धसमशीतोष्ण क्षेत्र यानी गांगेय क्षेत्र में गेहूं की केवल एक फसल ली जाती रही है, जिसे विंटर व्हीट यानी रबी की फसल कहते हैं और जिसे नवंबर से उगाकर मार्च–अप्रैल में काट लिया जाता है।

■ **डॉ. अनुराग शर्मा**

विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे अफ्रीका के किसी देश में नहीं बल्कि भारत में हैं। सरकार का कहना है कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर, जबकि अभी भी देश के 20 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में मौत का सबसे बड़ा कारण भूख है। भूख से लड़ने के लिए खाद्यान्न के सही वितरण के साथ उत्पादन भी बढ़ाना जरुरी है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकिकरण के कारण क्या खेती के लिए जमीन बढ़ाई जा सकती है? क्या भूख से लड़ने का सपना कभी साकार हो पाएगा? क्या मौजूदा क्षेत्रफल में ही अधिक उत्पादन लिया जा सकता है?

देश में गेंहू उत्पादन के क्षेत्र में हालिया शोध ने एक नई उम्मीद जगा दी है। जी हां हर भूखे को रोटी की उम्मीद।

देश में गेंहू की बढ़ती मांग को पूरा करने का नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर) के जेनेटिकल जिनोमिक्स लैबोरेटरी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुशील कुमार और उनकी टीम ने उल्लेखनीय पहल की है। प्रो. सुशील कुमार ने विश्व में पहली बार साल में दो बार गेंहू की फसल लेने में सफलता पा ली है और उनकी इस पहल से गेंहू की पैदावार में 25 से 66 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई है। हमसे विशेष बातचीत में प्रो. कुमार ने बताया कि अर्धशीतोष्ण जलवायु में गेहूं (ट्रिटीकम एस्टीवम) की, शरद काल और शीत ऋतु में, आगे–पीछे लगातार दो फसलें लेने पर ही उनका शोध केंद्रीत था जिसके बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उनके शोध में आगे–पीछे गेहूं की दो फसलें लेने के लिए अगेती फुलियाने के लिए आवश्यक आनुवंशिक उपस्कर को परिभाषित करना और भारत के गांगेय मैदानों में एक के बाद लगातार दूसरी फसल लेने के लिए गेहूं की नई किस्मों का विकास करना शामिल था। प्रो. सुशील कुमार के अनुसार एनआईपीजीआर स्थित खेतों में ही इस प्रकार का अध्ययन पांच वर्षों तक किया गया और नतीजे बेहद आशातीत रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व में पहली बार एक ही क्षेत्र से साल में दो बार गेंहू की फसल लेने के इस विचार को पेटेंट करने के लिए भेज दिया गया है और जर्नल ऑफ जेनेटिक्स के मार्च–अप्रैल अंक में इससे संबंधित शोधपत्र को छाप दिया गया है।

क्या है रिसर्च

इस क्रांतिकारी शोध के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रो. सुशील कुमार ने कहा कि अभी तक विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों (ठंड़े क्षेत्र) में दो तरह के गेहूं उगाए जाते हैं। कुछ बर्फीले इलाकों में शरद–शीत–बसंत–ग्रीष्म में विंटर व्हीट यानी शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है, जब कि अन्य समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्प्रिंगव्हीट

यानी बसंतकालीन फसल ली जाती है। हमारे देश में अर्धसमशीतोष्ण क्षेत्र यानी गांगेय क्षेत्र में गेहूं की केवल एक फसल ली जाती रही है, जिसे विंटर व्हीट यानी रबी की फसल कहते हैं और जिसे नवंबर से उगाकर मार्च–अप्रैल में काट लिया जाता है।

पूरे शोध में सबसे जरुरी था गेंहू की उन किस्मों का चयन करना जिनमें वर्नलाइजेशन और फोटोपीरिएड के प्रति संवेदनशीलता हो। आम तौर पर गेंहू की फसल को फुलियाने के लिए ठंड़े मौसम की जरुरत होती है इसे वर्नलाइजेशन यानी बासंतीकरण कहते हैं, और साथ फसल को पूरी तरह पकने के लिए लंबे फोटोपीरिएड यानी प्रकाशावधि की भी जरुरत होती है। शीतकालीन गेहूं बासंतीकरण (वर्नलाइजेशन) और प्रकाशावधि (फोटोपीरिएड) के प्रति तथा बसंतकालीन गेहूं प्रकाशावधि के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रो. सुशील कुमार की टीम के शोधकार्य से यह प्रदर्शित किया गया कि बसंतीकरण तथा प्रकाशावधि के प्रति असंवेदनशील गेहूं को भारत के गांगेय मैदानों में शरद ऋतु में यानी सितंबर से नवंबर तक उगाया जा सकता है। जबकि आमतौर पर देश में गेंहू को नवंबर के मध्य तक लगा दिया जाता है और फिर मार्च–अप्रैल में कटाई कर ली जाती है।

लेकिन एनआईपीजीआर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक में गेंहू की एक खास किस्म की बुआई 7 से 20 सिंतबर तक कर दी जाती है और यह किस्म 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पककर तैयार हो जाती है यानी 79 दिनों में फसल तैयार हो गई। शोध में पाया गया कि करीब 34 वें दिन में शदर काल में लगाई जाने वाली फसल फुलियाने लगती है और इसी कारण जल्द पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म पहले से ही मौजूद थी बस इसके बुवाई के समय में परिवर्तन किया गया है, अभी इस किस्म को नया नाम देने की तैयारी है फिलहाल इसे भद्रपाद व्हीट कहा जा रहा है।

प्रो सुशील कुमार ने बताया कि इसका कारण यह है कि वीआरएन–1 और पीपीडी–1ए उत्परिवर्तनों के बीच परस्पर पूरक अंतःक्रिया भारत के उत्तर–पश्चिमी गांगेय क्षेत्र की जलवायु में शरद ऋतु में सितंबर में बुआई करने पर गेहूं में फुलियाने की प्रक्रिया में लचीलापन ला देती है। इसी कारण से रबी की फसल से पहले भारत के गांगेय मैदानों में गेहूं की एक और फसल शरद ऋतु में लेने की संभावना ने अब मूर्त रूप ले लिया है।

गेंहू की दूसरी फसल की बुआई का समय 1 से 10 दिसंबर के बीच ही रखा गया और इसकी कटाई का समय 15 अप्रैल से 1 मई के बीच रहा। पहली फसल में गेंहू की पैदावार 3 से 4.5 टन प्रति हैक्टेयर रही थी जबकि गेंहू की दूसरी फसल से पैदावार 4 से 5 टन प्रति हैक्टेयर रही है। यानी गेंहू की एक बार ली जाने वाली फसल की तुलना में 170 फीसदी पैदावार में वृद्धि!!!

प्रो. कुमार का कहना है कि हमारी प्रयोगशाला में विकसित गेहूं के वंशक्रमों के इस गुण का उपयोग करके शरद तथा शीत ऋतु (रबी) के मौसम में एक के बाद दूसरी गेहूं की फसल लेने का सफल प्रदर्शन किया गया है। इसके लिए शरद ऋतु की गेहूं की फसल लेने के लिए बेहतर दृश्यप्ररूप विकसित किये गये हैं।

क्या है नई रिसर्च के फायदे

एनआईपीजीआर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस प्रकिया से देश में गेंहू उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव तो आएगा ही साथ ही गेंहू–धान के फसल चक्र से बाहर निकलकर किसान तिलहन–दलहन और गेंहू के फसल चक्र की ओर मुड़ेंगे। कुछ समय पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में उत्पादकता या तो समान बनी हुई है या फिर उसमें गिरावट देखी जा रही है। हरित क्रांति के कारण इन राज्यों में गहन कृषि का चलन शुरू हो गया था। और हरियाणा जैसे पारंपरिक तौर पर अर्धशुष्क प्रदेशों में पानी की अत्यधिक खपत वाली फसल धान के लगाने से इन इलाकों में पानी का स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है।

प्रो. कुमार का कहना है कि धान की बजाय गेंहू की फसल दो बार लेने के बावजूद इन क्षेत्रों में पानी की बचत होगी और साथ ही मिट्टी में उर्वरता बनी रहेगी। उनके शोध में गेंहू की सितंबर माह में लगाई जाने वाली फसल की पैदावार करीब 3.63 टन प्रति हैक्टेयर रही जबकि उसके बाद सर्दियों के मौसम में लगाई गई फसल की पैदावार करीब 5 टन प्रति हैक्टेयर रही है। इन दोनो फसलों को मिलाकर गेंहू की पैदावार करीब 9.1 टन प्रति हैक्टेयर रही है जबकि देश में गेंहू की प्रति हैक्टेयर पैदावार का औसत लगभग 2.6 टन है। पंजाब में गेंहू की औसत पैदावार करीब 4. 2 टन प्रति हैक्टेयार और हरियाणा में करीब 3.9 टन प्रति हैक्टेयर है।

भारत में करीब 93 फीसदी गेंहू की पैदावार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में होती है। देश में गेंहू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे अधिक करीब 34 फीसदी है, जबकि यहां उत्पादन का औसत करीब 2.6 टन प्रति हैक्टेयर है। इसके बाद गेंहू उत्पादन में पंजाब की करीब 19 फीसदी हिस्सेदारी, हरियाणा की करीब 13 फीसदी हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश 10 फीसदी, राजस्थान नौ फीसदी, बिहार पांच फीसदी, गुजरात चार फीसदी और अन्य की हिस्सेदारी लगभग छह फीसदी है।

गेंहू उत्पादन में देश की स्थिति

इस वर्ष देश में गेंहू का उत्पादन करीब 8.83 करोड़ टन होने का अनुमान है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विश्व में गेंहू उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है और चीन के बाद गेंहू का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है और इस मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। गेंहू के उत्पादन में भारत की वैश्विक स्तर पर हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी की है। एक अनुमान के मुताबिक देश में खाद्यान्न की मांग सन् 2025 तक करीब 29 करोड़ टन और सन् 2050 तक करीब 37 करोड़ टन प्रति वर्ष की हो जाएगी। वर्तमान में भारत में खाद्य उत्पादन करीब 23 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

एक देश जो बढ़ती प्रति व्यक्ति आय के दम पर तेजी विकास कर रहा है और राष्ट्र समृद्धि के पथ पर अग्रसर है लेकिन वहां खाद्यान्न, अनाज, दालों और तिलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जारी गिरावट गहन चिंता का विषय है। बीते समय में, हरित क्रांति के दौर में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता सन् 1951 के 144.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़कर 1991 में 186.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के स्तर तक पहुंच गई थी। चावल और गेंहू के लगभग दोगुने उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई 42.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की वृद्धि एक सार्थक वृद्धि थी।

लेकिन उम्मीद के विपरीत, सन् 1991 से प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 186.2 किलोग्राम प्रति वर्ष से गिरकर 2001 में 151. 9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के स्तर पर आ गई। इक्कीसवीं शताब्दी के पहले दशक में खाद्यान्न उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 160 किलोग्राम से नीचे ही बनी हुई है, बस 2008 में इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला जब यह आंकड़ा 159.2 किलोग्राम के स्तर को छू सका। अन्न, दालों और तिलहनों में लगातार गिरावट और साथ में कृषि पैदावार में जारी लगातार गिरावट 2012 में ही 120 करोड़ लोगों की आबादी का पेट भरना एक बड़ी चुनौती बनी ही हुई है, जबकि सन् 2026 में इस आबादी के 140 करोड़ के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।

खाद्यान्न उत्पादन में चुनौतियां

करीब 120 करोड़ की आबादी के लिए उपयुक्त और स्वस्थ्यकर आहार का उत्पादन करना एक मुश्किल चुनौती है। उल्लेखनीय है कि किसी भी आपात की स्थिति से निपटने के लिए भारत को अपनी खपत से अधिक उत्पादन करना पड़ता है जिससे वह अपने बफर स्टॉक यानी सुरक्षित भंडार को बनाए रख सके। पिछले कई वर्षों में देश अपने खाद्य उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने और उससे भी अधिक उत्पादन करने में सफल हुआ है, जिसका कारण न सिर्फ खेती लायक भूमि के क्षेत्रफल में इजाफा करना है बल्कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता भी बढ़ाना है। फिर भी समय बीतने के साथ अधिक उत्पादन लेना भी मुश्किल होता जाता है।

एक रोचक तथ्य है कि सिर्फ सन् 1973–74 से 1983–84 के दस वर्षों में ही 10 करोड़ टन के उत्पादन में पांच करोड़ अतिरिक्त उत्पादन जोड़ा गया। जबकि इसी चुनौती को पूरा करने के लिए 1984–85 से 2004–05 के दौरान दोगुना समय लगा। उत्पादन में गिरावट के ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले पांच करोड़ टन उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अपने कुल उत्पादन को 25 करोड़ टन करने के लिए 20 करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक समय लगेगा और आगे भी यही जारी रहेगा। अधिक उत्पादन लेने की चुनौती बड़ी से बड़ी होती जा रही है और समान क्षेत्रफल से उत्पादन लेने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। खेती लायक भूमि का रकबा बढ़ाने की तुलना में उत्पादन के लिए प्रमुखता से उत्पादकता ही कुंजी बन गई है।

पिछले एक दशक से 14 करोड़ हैक्टेयर भूमि ही खेती लायक बनी रही है। लोगो की बुनियादी खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए अगले दस वर्षों यानी 2009–10 से 2019–2020 तक चावल और गेंहू की उत्पादन दर में 30 से 40 फीसदी की वृद्धि करनी होगी। इस दौरान लोगो की बुनियादी खाद्य आवश्यकता पूरी करने के लिए 13 करोड़ टन चावल और 11 करोड़ टन गेंहू के स्तर पर उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होगी। चावल और गेंहू में 3 से 4 फीसदी की वृद्धिदर प्रति वर्ष बनाए रखना बेहद मुश्किल कार्य है। पहले भी देखा गया है कि मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए समान वृद्धिदर बनाए रखने में काफी परेशानी आई, इस वृद्धिदर को बनाए रखने के लिए गेंहू और चावल का क्षेत्रफल बढ़ाया गया जिससे मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन सन् 2001–10 के दशक ने हमें 1960 के उस दशक की याद दिला दी जब भारत का अस्तित्व शिप टू माउथ था यानी विदेश से जहाजों में भरकर गेंहू आता और बंदरगाह से सीधे अनाज मंडियों में भेज दिया जाता था।

हम बाहरी खाद्य मदद पर निर्भर थे जबकि उस समय हम आज की आबादी जो करीब 120 करोड़ लोग है, उससे भी आधी का पेट भरने में अस्मर्थ थे।

एनआईपीजीआर के अनुसंधान का महत्व

हाल ही में देश में बेकरी उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है, खासतौर

से दक्षिण भारत में, इस कारण गेंहू की मांग देश के दक्षिणी हिस्से से भी बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए भी जरुरी है कि गेंहू के उत्पादन में वृद्धि की जाए। भारत सरकार पिछली हरित क्रांति में छूट गए पूर्वी भारत से अब दूसरी हरित क्रांति की बात कर रही है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी कई तकनीकें मौजूद हैं जिससे पूर्वी भारत में धान का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इस पर काम शुरू भी हो गया है।

असल में अगर साल में दो बार गेंहू की फसल ली जाएगी तो बीच में धान की फसल लेना संभव नहीं होगा। इस लिए धान के लिए उपयुक्त पूर्वी और दक्षिण भारत में धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए और नई किस्मों के साथ नई तकनीकों को अपनाकर चावल का उत्पादन बढ़ाया जाए। जरूरी है कि पारंपरिक तौर पर गेंहू के लिए उपयुक्त उत्तर–पश्चिम भारत में गेंहू का उत्पादन बढ़ाया जाए और इसके लिए एनआईपीजीआर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रक्रिया गेंहू उत्पादन में क्रांतिरिी परिवर्तन ला सकती है।

एनआईपीजीआर के प्रो. सुशील कुमार का कहना है कि विश्व भर में अब गेंहू की ऐसी किस्मों पर काम चल रहा है जिसमें बालियों का आकार बड़ा हो और इन बालियों के बोझ को सहने की क्षमता भी गेंहू पौधे के तने में भी हो। उनका कहना है कि अभी गेंहू के पौधे में करीब 40 से 45 फीसदी वजन गेंहू की बालियों का होता था, अब कोशिश की जा रही है कि करीब 60 से 65 फीसदी वजन बालियों का हो। इसके लिए मजबूत तने वाले गेंहू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो इन भारी बालियों का वनज भी सह सकें और तेज हवा में गिरे भी नहीं। यानी पहले आई हरित क्रांति में बौने गेंहू ने बाजी मारी थी अब फिर से शोध मजबूत और लंबे गेंहू की प्रजाति ओर मुड़ गया है।

प्रो. सुशील कुमार का कहना है कि दोनो प्रकार के गेंहू का बीज भी तैयार है और अगले रबी सीजन में आसपास के करीब 540 किसानों को देकर, पैदावार भी बढ़ाने की तैयारी है और नए बीज बनाने की भी। हालांकि, दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा संस्थान सितंबर माह में इस गेहूं को बो कर प्रोफेसर सुशील कुमार की रिसर्च की जांच करेंगे और उम्मीद है कि करनाल स्थित गेंहू अनुसंधान निदेशालय भी इस साल अपनी रपोर्ट दे देगा। नई किस्म पर संस्थानों की मंजूरी की मोहर लगने के बाद किसानों के इस किस्म को जल्द जारी कर दिया जाएगा।

प्रो. कुमार और उनकी टीम ने खाद्य सुरक्षा के लिए पूरे विश्व को एक नई राह प्रदान कर दी है। जरुरत है कि देश में भी इन उपायों को अपनाकर भुखमरी से जूझ रही आबादी को रोटी दी जाए और भारत को बच्चों और महिलाओं में कुपोषण के कलंक से मुक्ति दिलाई जाए। वैज्ञानिकों ने अपना कार्य कर दिया है और काम आगे भी जारी है, लेकिन क्या नीति निर्धारक अपनी भूमिका समझेंगे? ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

जीएम बीजों के घातक परीक्षण

जीएम फसलों के विरोध का मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं और यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को स्वतंत्र विज्ञान मंच ने सारगर्भित ढंग से रखा है। इस पैनल में एकत्र हुए अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है कि जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं और ये फसलें खेतों में समस्याएं बढ़ा रहीं हैं।

■ भारत डोगरा

जेनेटिक दृष्टि से संवर्धित या मोडिफाइड जीएम फसलों को खुली छूट देने या उनके व्यापारिक स्तर के प्रसार की छूट देने के खतरों के बारे में अब समझ तो व्यापक बन गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इनका छोटे स्तर पर खेतों में परीक्षण भी खतरनाक हो सकता है।

यह स्थिति जेनेटिक प्रदूषण के कारण पैदा होती है जो छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल सकता है। इस खतरे के बारे में जानकारी के अभाव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट से दूर किया है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह खतरा उस स्थिति में और बढ़ सकता है, जब जीएम फसलों के प्रसार और परीक्षणों की नियमन व्यवस्था कमजोर हो। भारत में यह नियमन का काम जैव तकनीकी (बॉयो टेक्नोलॉजी) को दिया गया है, जो जीएम फसलों के प्रसार को अपना काम मानता है। जो विशेषज्ञ खुद जीएम फसलों के प्रसार से जुड़े हैं, उन्हें नियामक कैसे बताया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट की समिति ने नियमन का काम बायो टेक्नालॉजी विभाग से लेकर स्वास्थ्य या पर्यावरण मंत्रालय को देने की संस्तुति की है। समिति ने कहा है कि जब तक नियमन की कमियां दूर न हो जाएं तब तक जीएम फसलों के खेतों में परीक्षणों या फील्ड ट्रायल पर रोक लगनी चाहिए। बीटी फसलों के ऐसे परीक्षणों पर 10 वर्ष की रोक लगनी चाहिए। जो फसलें मूलतः भारत की ही हैं, उनके जीएम परीक्षणों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की समिति की ये संस्तुतियां पर्यावरण व खेती सहित राष्ट्रीय हित में हैं। इनके महत्व को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जेनेटिक प्रदूषण खतरा कितना गंभीर है।

जीएम फसलों के विरोध का मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं और यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों

जीएम फसलों को अब दृढ़ता से अस्वीकार कर देना चाहिए। इन फसलों के खतरे का सबसे अहम पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है।

में फैल सकता है। इस विचार को स्वतंत्र विज्ञान मंच ने सारगर्भित ढंग से रखा है। इस पैनल में एकत्र हुए अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है कि जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं और ये फसलें खेतों में समस्याएं बढ़ा रहीं हैं।

अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता। अतः जीएम व गैर जीएम फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं, जिनसे इनकी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति होगी। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से अस्वीकार कर देना चाहिए।

इन फसलों के खतरे का सबसे अहम पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। जानी–मानी बॉयोकेमिस्ट व पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर सूसन बारडोक्ज ने कहा है, अब तक की तमाम तकनीकें ऐसी थीं, जो नियंत्रित हो सकती थीं, पर मानव इतिहास में जीएम पहली तकनीक है, जिससे खतरा पैदा हो गया तो इस क्षति को रोका नहीं जा सकता और क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती है।

जब एक जीएम ऑर्गेनिज्म या को रिलीज कर दिया जाता है तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जेनेटिक फसलों के प्रसार से खरपतवार तेजी से फैल सकते हैं और सामान्य फसलों में जेनेटिक प्रदूषण का प्रतिकूल असर हो सकता है। बहुत से देश ऐसे खाद्य पदार्थ चाहते हैं, जो जीएम फसलों के असर से मुक्त हों। यदि जीएम फसलों का हमारे यहां प्रसार होगा तो इन देशों का बाजार हमसे छिन जाएगा। स्टारकार्न नाम की मक्का की जीएम फसल को लौटाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पर भी पूरी सफलता नहीं मिली।

कृषि व खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी मात्र छह–सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों व विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिये विश्व कृषि व खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है, जैसा विश्व इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।

बीटी बैगन विवाद के समय 2009–10 में यह सामने आया था कि भारत में जीएम फसल नियमन–व्यवस्था कमजोर है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों से प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैव तकनीक के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रो. पुष्प भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के काम पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया। प्रो. पुष्प भार्गव सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर बॉयोलॉजी, हैदराबाद के पूर्व निदेशक रहे और नैशनल नॉलेज आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं।

प्रो. भार्गव ने बताया कि बीटी बैंगन के सीमित एन्वायरमेंटल रिलीज के लिए भी करीब 30 परीक्षण की जरूरत थी, जबकि किए गए 10 से भी कम। ये परीक्षण भी एक कंपनी ने ही खुद किए और उसके पास इसके पूर्ण मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। इन प्रयोगों में कई गलतियां थी। कई वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की। बीटी बैंगन विवाद के समय विश्व के 17 विख्यात वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा कि भारत के सरकारी रेग्यूलेटर स्वतंत्र जैव–सुरक्षा टेस्ट को जरूरी नहीं मानते। जो कंपनी अपने जीएम उत्पाद के व्यापारिक प्रसार की स्वीकृति लेना चाहती है, उसके अनुसंधान को ही बिना आलोचना के सुरक्षा का प्रमाण मान लिया जाता है।

इस पत्र में इन कंपनियों द्वारा किए गए अनुसंधान की गंभीर विसंगतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैरी स्मिथ ने अपनी चर्चित पुस्तक जेनेटिक रुलेट में विस्तार से बताया है कि विश्व स्तर पर अपने उत्पादों पर कंपनियों द्वारा जो टेस्ट किए जाते हैं, वे नाममात्र के ही वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह पेश किया जाता है कि समस्याएं सामने न आएं। कभी सैंपल साइज बहुत छोटा रखा जाता है तो कभी तुलनाएं ठीक से नहीं की जाती और कभी स्वास्थ्य समयाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

ससेक्स विश्वविद्यालय में विज्ञान नीति करे प्रोफेसर एरिट मिलस्टोन ने कहा है कि जीएम खाद्यों का ठीक से परीक्षण नहीं किया गया। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जीएम फसलों का थोड़ा–बहुत प्रसार व परीक्षण भी बेहद घातक हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि उन फसलों को थोड़ा बहुत उगाने से उत्पादकता बढ़ने के नतीजे मिलेंगे या नहीं। मूल मुद्दा यह है कि इनसे जो सामान्य फसलें हैं, वे भी प्रदूषित हो सकती हैं। यह जेनेटिक प्रदूषण बहुत तेजी से फैल सकता है व इस कारण जो क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ❑

चक्रव्यूह में फंसे किसान

अपने देश में 1995 से 2011 के बीच दो लाख नब्बे हजार से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनके इस हाल को देखकर अभिमन्यु की याद आ जाना स्वाभाविक ही है। किसानों के समक्ष चक्रव्यूह की रचना कृषि–रासायनिक उद्योग जगत और असंवेदनशील वैज्ञानिक समुदाय ने की है। उनके सामने विकल्प बहुत खतरनाक हैं। उन्हें मालूम है कि देर–सबेर उन्हें भी मौत को गले लगाना पड़ेगा या फिर खेती–किसानी छोड़ देनी होगी।

■ देविन्दर शर्मा

महाभारत में अभिमन्यु की कथा से सभी परिचित हैं, जिसने चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो भलीभांति मालूम थी, लेकिन यह नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे निकला जाए? अनेक अर्थों में आज भारतीय किसानों की हालत अभिमन्यु सरीखी ही नजर आती है।

महाभारत में अभिमन्यु की कथा से सभी परिचित हैं, जिसने चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो भलीभांति मालूम थी, लेकिन यह नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे निकला जाए? अनेक अर्थों में आज भारतीय किसानों की हालत अभिमन्यु सरीखी ही नजर आती है। उन्हें चक्रव्यूह में घुसने के लिए मजबूर कर दिया गया है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि इससे कैसे बाहर आया जाए। अभिमन्यु की तरह वे भी बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन अंततरू उनके संघर्ष की वही परिणति होनी है जो महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की हुई थी।

अपने देश में 1995 से 2011 के बीच दो लाख नब्बे हजार से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनके इस हाल को देखकर अभिमन्यु की याद आ जाना स्वाभाविक ही है। किसानों के समक्ष चक्रव्यूह की रचना कृषि–रासायनिक उद्योग जगत और असंवेदनशील वैज्ञानिक समुदाय ने की है। उनके सामने विकल्प बहुत खतरनाक हैं। उन्हें मालूम है कि देर–सबेर उन्हें भी मौत को गले लगाना पड़ेगा या फिर खेती–किसानी छोड़ देनी होगी।

फसल उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर जिस संवेदनहीन कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है वह जमीन की उर्वरता को बर्बाद कर रही है, वातावरण को प्रदूषित कर रही है, भूमिगत जल को तेजी से घटा रही है और कुल मिलाकर खेती को घाटे का सौदा बनाने पर आमादा है।

जाहिर है, इन स्थितियों में किसानों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज हम अपनी कृषि में जो बर्बादी का माहौल देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण रासायनिक पदार्थों का अवांछित और अविचारित इस्तेमाल है। रासायनिक कीटनाशकों को ही लें।

1970 के दशक के अंतिम दौर में ही कार्नेल यूनिवर्सिटी के डेविड पिमेंटन ने अपने एतिहासिक शोध पत्र में यह कह दिया

था कि 99.9 प्रतिशत कीटनाशक वातावरण में समा जाते हैं और केवल 0.01 फीसद ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस चेतावनी के बावजूद कृषि वैज्ञानिक रासायनिक कीटनाशकों की वकालत करने में लगे हुए हैं। इससे कीटनाशक बनाने वाले उद्योगों की तो चांदी है, लेकिन किसान और बेचारे उपभोक्ता मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं।

इससे यह सवाल उभरता है कि क्या हमारे किसान कभी भी कीटनाशकों के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकेंगे? व्यावहारिक विकल्पों की तलाश में मैं दुनिया भर में घूमा हूं। मैंने उन किसानों को देखा भी है और उनके साथ काम भी किया है जो रसायनों के इस्तेमाल के बिना फसल उपजाने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं।

अपने देश में ही अनेक स्थानों पर और यहां तक कि आंध्र प्रदेश (जहां 35 लाख एकड़ जमीन पर बिना रसायनों के फसलों का उत्पादन हो रहा है) के बाहर भी किसान अनेक पहल आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ये पहल उम्मीद की किरण जगाती हैं।

पिछले दिनों मैंने जींद जिले के दो छोटे गांवों का दौरा किया। यहां के किसान और गांव की महिलाएं एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वे न केवल कपास की फसल पर रसायनों का इस्तेमाल करते, बल्कि जैव–रसायनों के इस्तेमाल से भी परहेज करते हैं। उन्होंने कीटों के बीच ऐसा संतुलन कायम कर दिया है कि जो कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए लाभदायक कीट उपलब्ध हैं। जींद जिले के एक गांव निदाना की कहानी बतानी जरूरी है। कपास का उत्पादन करने वाले किसी किसान से खटमल जैसे एक फुसफुसे कीड़े के बारे में पूछिए तो वह रो पड़ेगा। इसी कीट के बारे में किसी कीटनाशक उत्पादक से पूछिए तो वह मुस्करा देगा। यह छोटा सा कीट कपास किसानों के लिए दुश्मन बनकर उभरा है। इस अकेले कीट ने कीटनाशक उद्योग को कई अरब रुपये का बना दिया है।

फसल उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर जिस संवेदनहीन कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है वह जमीन की उर्वरता को बर्बाद कर रही है, वातावरण को प्रदूषित कर रही है, भूमिगत जल को तेजी से घटा रही है और कुल मिलाकर खेती को घाटे का सौदा बनाने पर आमादा है।

निदाना की अशिक्षित अथवा कम शिक्षित महिलाओं और उद्यमी किसानों के लिए यह कीट कोई खतरा नहीं है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी फसलों पर लगने वाले सभी कीटों की भलीभांति पहचान कर ली है। किसान और महिलाएं यह जान गई हैं कि कौन से कीट उनके लिए लाभदायक हैं और कौन से फसल को नष्ट करने वाले। उन्होंने कीटों के उस चक्र पर अपना ध्यान लगाया जो फसलों को नष्ट करने वाले कीटों को मिटाने में सहयोग देने वाला है।

उन्होंने यह समझ लिया कि कपास की फसल के लिए जो कीट सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है उसे नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन दर्जन प्रजातियों के कीट, पतंगे मौजूद हैं। मैं उस समय चकित रह गया जब गांव की एक बुजुर्ग महिला मुझे दिखाने के लिए कुछ कीट और भौंरे अपने साथ ले आई। उन्होंने बताया कि हम जिस कीट की समस्या का सामना कर रहे थे उस पर दूसरे कीटों के जरिये हमने नियंत्रण कर लिया। उनके लिए लाभदायक कीटों का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हरियाणवी में एक लोकगीत तैयार किया गया है जिसमें उन कीटों से आकर फसल बचाने का आग्रह किया जाता है जो फसल को नष्ट करने वाले कीटों का काम तमाम करते हैं। निदाना का प्रयोग 2007 में शुरू हुआ।

निश्चित रूप से किसानों को यह समझाना कठिन था कि वे रासायनिक कीटनाशकों के बिना भी अपनी फसल उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन हर गुजरते साल के साथ अधिक से अधिक किसान अब कीटनाशकों के बिना फसल पैदा करने की प्रणाली अपना रहे हैं। कम से कम कृषि वैज्ञानिकों को इस पहल पर ध्यान देना चाहिए और प्रयोगशाला से जमीन तक के अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह पलट देना चाहिए। उन्हें जमीन से प्रयोगशाला की नीति अपनानी होगी, तभी हमारे किसानों की त्रासदी के अंत की शुरुआत होगी। ❑

कपास की फसल के लिए जो कीट सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है उसे नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन दर्जन प्रजातियों के कीट, पतंगे मौजूद हैं। मैं उस समय चकित रह गया जब गांव की एक बुजुर्ग महिला मुझे दिखाने के लिए कुछ कीट और भौंरे अपने साथ ले आई। उन्होंने बताया कि हम जिस कीट की समस्या का सामना कर रहे थे उस पर दूसरे कीटों के जरिये हमने नियंत्रण कर लिया। उनके लिए लाभदायक कीटों का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है।

महंगाई की मुश्किल कैसे हो कम!!

जापान की राजधानी टोक्यो में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रतिदिन 80 लाख लोगों को लाभान्वित करती है। इसी तरह दुनिया के कई चमकीले शहरों जैसे लंदन, सिंगापुर, सिडनी आदि में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग कार्यालय आने–जाने में सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करते हैं। हमें देश के सभी शहरों में कारगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। देश में करीब पांच हजार शहरों में कारगर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था लोगों के आवागमन खर्च को कम कर सकती है। निसंदेह ऐसे कदमों से देश में करोड़ों लोगों को मूल्यवृद्धि की पीड़ा से राहत दिलाई जा सकेगी।

■ **जयंतीलाल भण्डारी**

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई 10 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए 7.81 फीसद हो गई है। इस ऊंची महंगाई दर का कारण सितम्बर माह में गेहूं, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, शक्कर, सब्जी और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना बताया गया है।

24–27 सितम्बर के बीच 'ग्लोबल रिसर्च इप्सोस' द्वारा 'मूड ऑफ द नेशन' सव्रे किया गया था। उसके मुताबिक 78 फीसद से अधिक लोगों ने यह माना कि इस बार त्योहारों पर बढ़ती महंगाई की वजह से वे बहुत संभलकर खर्च करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वर्ष 2012–13 की मैक्रो इकोनॉमिक एंड मानिटरी डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अन्य विकासशील देशों की तुलना में खाद्य महंगाई दर दोगुनी है और अर्थव्यवस्था में अभी महंगाई बढ़ने की प्रवृत्ति मौजूद है।

वस्तुतः इस समय देश में महंगाई आंतरिक कारणों के साथ–साथ वैश्विक कारणों से भी प्रभावित हो रही है। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी देश में भी खाद्य महंगाई को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका में भयावह सूखे के कारण खाद्यान्न आयातक देशों के द्वारा अनाज की बड़े पैमाने पर अग्रिम खरीद की जा रही है।

अमेरिका के 48 राज्यों के 60 फीसद इलाकों में सूखा पड़ चुका है। वर्ष 1956 के बाद का यह अमेरिका का सबसे बड़ा सूखा है। चीन भी सूखे को लेकर चिंतित है क्योंकि चार वर्ष पहले उसे जिस खाद्यान्न आयात के कारण खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ा था, उसी तरह उसे अब ज्यादा खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है। रूस में भी खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति ठीक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन भी कम बारिश के कारण खाद्यान्न संकट का

वस्तुतः इस समय देश में महंगाई आंतरिक कारणों के साथ–साथ वैश्विक कारणों से भी प्रभावित हो रही है। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी देश में भी खाद्य महंगाई को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका में भयावह सूखे के कारण खाद्यान्न आयातक देशों के द्वारा अनाज की बड़े पैमाने पर अग्रिम खरीद की जा रही है।

सामना कर रहे हैं।

हालांकि खाद्यान्न की बढ़ती कीमत में अमेरिका और अन्य विकसित देशों के बायो– फ्यूल का भी हाथ है।

स्थिति यह है कि दुनिया में खाद्यान्न की महंगाई ठीक उसी तरह नजर आ रही है, जैसी 2008 के वैश्विक खाद्यान्न संकट के समय थी। वस्तुतः हमारे देश में पिछले दो–तीन वर्षों में महंगाई धीरे–धीरे बढ़ती रही है। अब अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है कि महंगाई दर ऊंची है, ब्याज दर भी ऊंची है, साथ ही विकास दर में भी गिरावट है। ऐसे में अब केवल आरबीआई के मौद्रिक कदमों से महंगाई का मामला सुलझने वाला नहीं है।

महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि अब देश में आर्थिक सुधारों का दूसरा दौर शुरू हो गया है और इसके कारण विभिन्न सब्सिडियां कम होने से लोगों को महंगाई का अहसास और अधिक होगा। ऐसे में जहां सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रंण के रणनीतिक प्रयास जरूरी होंगे, वहीं लोगों को भी महंगाई से निबटने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे।

हम खाद्यान्न की बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया से सबक ले सकते हैं। मौजूदा वर्ष में कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया भी कमोबेश महंगाई की भारत जैसी ही समस्या का सामना कर रहा था। वह बढ़ते मूल्यों के साथ ऊंची ब्याज दर और मंदी से जूझ रहा था। इस स्थिति से निपटने और महंगाई पर नियंत्रण के ठोस उपायों को बताने हेतु दक्षिण कोरिया के नॉलेज इकोनामी मंत्रालय ने एक कार्यबल गठित किया था। इस कार्यबल ने पाया कि कुछ बड़े कारोबारियों ने गैस स्टेशनों के साथ सौदे करके ईधन की खुदरा कीमतों को

महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि अब देश में आर्थिक सुधारों का दूसरा दौर शुरू हो गया है और इसके कारण विभिन्न सब्सिडियां कम होने से लोगों को महंगाई का अहसास और अधिक होगा। ऐसे में जहां सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रंण के रणनीतिक प्रयास जरूरी होंगे, वहीं लोगों को भी महंगाई से निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। हम खाद्यान्न की बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया से सबक ले सकते हैं। मौजूदा वर्ष में कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया भी कमोबेश महंगाई की भारत जैसी ही समस्या का सामना कर रहा था।

वास्तविक कीमत से कहीं ऊपर कर दिया था। इसी तरह कई और कारोबारियों ने जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति में गतिरोध डालकर उनकी कीमतें बढ़ा दी थी। कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कड़े नियमों और कठोर कार्रवाइयों से आपूर्ति क्षेत्र के गतिरोधों को तत्काल दूर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण कोरिया में अब खाद्यान्न कीमतों पर नियंत्रण दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया में सितम्बर 2012 में महंगाई दर दो फीसद के इर्दगिर्द ही रही है। निश्चित रूप से इस समय भारत में खाद्यान्न के पर्याप्त उत्पादन के बाद भी महंगाई की जो स्थिति है उसके लिए काफी हद तक आपूर्ति क्षेत्र की समस्याएं जिम्मेदार हैं। खाद्यान्न की थोक व फुटकर कीमतों में अंतर पहले की तुलना में बढ़ा है, स्टॉकिस्ट व सटोरिए बाजार पर हावी हैं।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खाद्यान्न उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ भारी मुनाफा लेते हुए मूल्य वृद्धि का कारण बने हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही है। ऐसे में सरकार को खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करने, मध्यस्थों के मुनाफे को कम करने तथा आपूर्ति बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की तरह कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को खुले बाजार में खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित किए जाने वाले अनाज का वितरण लाभार्थियों तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब दाल, खाद्य तेल और चीनी की भंडारण सीमा तय की जानी चाहिए। चूंकि स्टॉक लिमिट का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, इसलिए राज्यों को महंगाई थामने में केंद्र की मदद करनी चाहिए। चूंकि कृषि जिंसों के वायदा बाजार में सटोरिए पूरी तरह सक्रिय हैं, इसलिए कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध जरूरी है।

इस समय उड़द, अरहर व चावल के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध है, लेकिन गेहूं, चीनी, सोया तेल, सरसों बीज, सोयाबीन आदि कृषि जिंसों का वायदा खुला हुआ है। अतः इन आवश्यक कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर रोक लगाई जानी चाहिए। कृषि जिंसों की कीमतें बढ़ने से संबंधित अधिकांश अध्ययन रिपोर्ट्स में यह निष्कर्ष उभरकर आ रहा है कि भारत में जबसे कृषि जिंसों का वायदा व्यापार शुरू किया गया है, तभी से खाद्यान्नों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

यह उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से भारत ही नहीं

अमेरिका व दुनिया के दूसरे विकसित देश भी प्रभावित हो रहे हैं। इन देशों के लोग पेट्रोल, डीजल व गैस की महंगाई से बचने के लिए साइकिलों का उपयोग बढ़ा रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में एक योजना बन रही है, जिसके तहत शहर में 15 हजार साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन्हें कोई भी किराए पर लेकर इस्तेमाल कर सकेगा। यूरोप और चीन में भी पेट्रोल और डीजल की मूल्यवृद्धि से बचाव के लिए लोग खूब साइकिलिंग कर रहे हैं। हम भारत में भी पेट्रोल–डीजल की कीमतों से राहत हेतु कम दूरी के लिए साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहन दे सकते हैं। अधिक दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे लोगों को

लंदन, सिंगापुर, सिडनी आदि में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग कार्यालय आने–जाने में सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करते हैं। हमें देश के सभी शहरों में कारगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है।

परिवहन संबंधी खर्च में कमी का लाभ मिल सकेगा।

गौरतलब है कि दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। उदाहरण के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रतिदिन 80 लाख लोगों को लाभान्वित करती है। इसी तरह दुनिया के कई चमकीले शहरों जैसे लंदन, सिंगापुर, सिडनी आदि में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग कार्यालय आने–जाने में सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करते हैं। हमें देश के सभी शहरों में कारगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है।

देश में करीब पांच हजार शहरों में कारगर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था लोगों के आवागमन खर्च को कम कर सकती है। निसंदेह ऐसे कदमों से देश में करोड़ों लोगों को मूल्यवृद्धि की पीड़ा से राहत दिलाई जा सकेगी। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

सवाल

नकद सब्सिडी पर सवाल

हमें आधार के दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को मासिक पेंशन दे देनी चाहिए। खाद्य, खाद, एलपीजी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम सब्सिडियों से जनता को मुक्त कर देना चाहिए। प्रोविडेंट फंड की तरह एक संस्था को यह कार्य दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए जनता के फिंगर प्रिंट एकत्रित करना जरूरी नहीं है। विपक्ष को जागना चाहिए. . .आधार के माध्यम से अब संप्रग देश के गर्भगृह को विदेशियों के लिए खोलना चाहती है। विपक्ष को चाहिए कि हर नागरिक के लिए मासिक पेंशन की मांग करने के साथ–साथ व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने का विरोध करे।

■ **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

केंद्र सरकार ने सब्सिडी को लाभार्थियों को नकद देने के लिए आधार नंबर का सहारा लिया है। आधार संगठन द्वारा देश के हर नागरिक के फिंगर प्रिंट, आंख की पुतली का फोटो, चेहरे का फोटो तथा पता रखा जाएगा। लाभार्थी की शारीरिक पहचान होने से उसको मिलने वाली सुविधा को हड़पा नहीं जा सकेगा, जैसे वर्तमान में सरकारी गल्ले की दुकान के दुकानदार तमाम लाभार्थियों के राशन कार्ड रख लेते हैं। इनके नाम से चीनी आदि की बिक्री दिखा कर ब्लैक करते हैं।

आधार नंबर लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि राशन की दुकान पर मशीन लगी होगी। यह मशीन दुकान पर खड़े ग्राहक के फिंगर प्रिंट को आधार के कम्प्यूटर में पड़े फिंगर प्रिंट से मिलाएगी। मिलने पर ही दुकानदार को बिक्री की स्वीकृति दी जाएगी। आधार के माध्यम से गैस की सब्सिडी भी नकद दी जा सकेगी। आधार नंबर के साथ अभ्यर्थी का बैंक खाता जुड़ा रहेगा।

वर्तमान में आपको एक वर्ष में गैस के छह सिलेंडर मिलने हैं। सिलेंडर का बाजार भाव 900 रुपये है, जबकि सब्सिडी में यह लगभग 450 रुपये में उपलब्ध है। आपको 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 2700 रुपये की सब्सिडी मिलनी है। यह सब्सिडी सीधे खाते में जमा करा दी जाएगी और सिलेंडर बाजार भाव में 900 रुपये में खरीदने होंगे। इसी प्रकार खाद पर मिलने वाली सब्सिडी किसान के खाते में सीधे जमा करा दी जाएगी और उसे खाद बाजार भाव पर खरीदनी होगी।

अध्ययनों से साबित हुआ है कि सब्सिडी का आधा हिस्सा ही लाभार्थी तक पहुंचता है। शेष सब्सिडी सरकारी कर्मचारियों, कंपनियों एवं दुकानदारों द्वारा हड़प ली

नए शहर में बैंक खाता खोलने अथवा मोबाइल फोन लेने के लिए उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा, जिससे परिजनों को पता लग जाएगा कि वे कहां हैं? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गोपाल कृष्ण बताते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के कारण आधार जैसी योजनाओं को रद किया गया है। इंग्लैंड के गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता की सेवक के रूप में रहना चाहती है, न कि जनता को हंटर से हांकने वाले दादा के रूप में।

जाती है। आधार के लागू होने पर यह धांधली समाप्त हो जाएगी। सब्सिडी के नकद वितरण में लाभार्थी का सम्मान है। लाभार्थी को छूट रहेगी कि मिली रकम का उपयोग किस प्रकार करे।

वर्तमान में आपको चीनी की जरूरत न हो तो सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप राशन दुकान से चीनी खरीद कर दूसरे दुकानदार को बेचते हैं। नगद वितरण से आपको चीनी, सिलेंडर अथवा खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ समाजशास्त्री नकद हस्तांतरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रकम के दुरुपयोग की संभावना है।

भारत सरकार द्वारा आधार लागू करने का कार्य उस अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया है, जो अमेरिकी रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई है। यद्यपि सरकार ने दावा किया है कि आधार की जानकारी भारतीय कंप्यूटरों में ही रहेगी, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है। आधार के दो पक्ष हैं। सब्सिडी के नगद वितरण की योजना अच्छी है, परंतु इसे लागू करने के लिए लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन तथा देश की जानकारी को विदेशियों के हाथ में दिया जा रहा है।

वर्तमान में सब्सिडी का दुरुपयोग करने के लिए आपको काफी समय और श्रम करना होगा। एक दुकानदार से खरीदकर दूसरे को बेचना होगा। आधार लागू होने के बाद आप आसानी से बैंक से रकम निकालकर मनचाहा उपयोग कर सकेंगे। मैं लाभार्थी की इस स्वतंत्रता को अच्छा मानता हूं। अल्प संख्या में हर समाज में दुराचारी होते हैं। इन मुट्ठी भर दुराचारियों के नाम पर पूरे समाज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आधार के माध्यम से मनरेगा आदि की रकम कुछ राज्यों में वितरित करना शुरू कर दिया गया है। इन्हें लागू करने में कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जैसे लाभार्थी के फिंगर प्रिंट कंप्यूटर में दर्ज फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। इन समस्याओं को एक निश्चित कालखंड में दूर किया जाएगा।

आधार कार्यक्रम में समस्या दूसरे स्तर पर है। देश के नागरिकों पर सरकार की चौतरफा नजर रहेगी। मान लीजिए आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं। रेल टिकट बुक कराने में आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। इससे सरकार को पता चल जाएगा कि कौन–कौन आंदोलन में भाग ले रहा है। अथवा मान लीजिए कि किन्हीं प्रेमियों ने घर छोड़ने का मन बनाया।

नए शहर में बैंक खाता खोलने अथवा मोबाइल फोन लेने के लिए उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा, जिससे परिजनों को पता लग जाएगा कि वे कहां हैं?

मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गोपाल कृष्ण बताते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के कारण आधार जैसी योजनाओं को रद किया गया है। इंग्लैंड के गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता की सेवक के रूप में रहना चाहती है, न कि जनता को हंटर से हांकने वाले दादा के रूप में। फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतंत्रता के हनन के आधार पर ऐसी योजना को रद किया था। जर्मनी में नागरिकों की इसी प्रकार की सूचना अमेरिकी कंपनी आइबीएम ने एकत्रित की थी। बाद में हिटलर ने आइबीएम से इस जानकारी को प्राप्त किया और इसका उपयोग कुछ लोगों की पहचान और नरसंहार के लिए किया।

कुछ समाजसेवियों का मानना है कि होस्नी मुबारक ने मिस्र के नागरिकों की ऐसी जानकारी तख्तापलट के पहले अमेरिका को दे दी थी। दूसरी समस्या है कि भारत सरकार द्वारा आधार लागू करने का कार्य उस अमेरिकी कंपनी को सौंपा गया है, जो अमेरिकी रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई है। यद्यपि सरकार ने दावा किया है कि आधार की जानकारी भारतीय कंप्यूटरों में ही रहेगी, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है। आधार के दो पक्ष हैं। सब्सिडी के नगद वितरण की योजना अच्छी है, परंतु इसे लागू करने के लिए लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन तथा देश की जानकारी को विदेशियों के हाथ में दिया जा रहा है।

हमें आधार के दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को मासिक पेंशन दे देनी चाहिए। खाद्य, खाद, एलपीजी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम सब्सिडियों से जनता को मुक्त कर देना चाहिए। प्रोविडेंट फंड की तरह एक संस्था को यह कार्य दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए जनता के फिंगर प्रिंट एकत्रित करना जरूरी नहीं है। विपक्ष को जागना चाहिए। पिछले चुनाव में संप्रग सरकार ने मनरेगा और ऋण माफी को हथकंडा बना सत्ता हासिल की और परमाणु संधि लागू की थी। आधार के माध्यम से अब संप्रग देश के गर्भगृह को विदेशियों के लिए खोलना चाहती है। विपक्ष को चाहिए कि हर नागरिक के लिए मासिक पेंशन की मांग करने के साथ–साथ व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने का विरोध करे। ❑

दृष्टिकोण

रिवर्ज बैंक की मृगमरीचिका

भारतीय रिजर्व बैंक हर माह जब अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करता है तो आर्थिक विश्लेषक हमेशा यह अपेक्षा लगाकर रखते हैं कि इस बार तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाने का काम करेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। 30 अक्टूबर को घोषित मौद्रिक नीति से भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले दो वर्षों से ब्याज दरों में लगातार वृद्धि के बावजूद महंगाई की दर थमने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन रिजर्व बैंक की मृग मरीचिका का कोई अंत ही नहीं है।

■ **डॉ. अश्विनी महाजन**

गत 30 अक्टूबर को घोषित मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को न घटाकर एक बार फिर उन सभी को निराश किया है, जो ऐसी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि रिजर्व बैंक ने नकद अनुपात घटाकर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने का मामूली प्रयास तो किया है, लेकिन ब्याज दरों को घटाते हुए उधार को सस्ता करने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से औद्योगिक विकास की दर लगातार घटती हुई शून्य के आसपास पहुंच रही है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है और ग्रोथ लगातार गिर रही है। आइएमएफ सरीखी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस वर्ष आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 4.9 प्रतिशत कर चुकी हैं और इसी प्रकार से सरकार की ग्रोथ की ऊंची दर के प्रति आशावान नहीं हैं।

पिछले दस सालों में दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रोथ की दर 8 प्रतिशत के आसपास रही। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले ही वर्ष में जीडीपी की संवृद्धि दर में इतनी भारी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं हैं। इससे आम आदमी की आय में वृद्धि की संभावनाएं तो समाप्त होती ही हैं, देश में वस्तुओं, सेवाओं और यहां तक की मकानों की मांग भी कम होने की आशंका है।

यही नहीं, उत्पादन कम होने से महंगाई की दर जो पहले से ही करीब 8 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, और अधिक भयंकर रूप धारण कर सकती है। सरकार इस मंदी से निपटने के लिए तरह–तरह के उपायों की घोषणा करती रही है।

हमारे नीति–निर्माताओं की सोच कुछ इस प्रकार की है कि यदि अर्थव्यवस्था में कोई भी खराबी हो तो उसका एक रामबाण इलाज विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है और इस नाते सरकार ने राजनीतिक विरोधों को भी दरकिनार करते हुए खुदरा, बीमा और पेंशन फंडों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणाएं कर डाली।

वर्ष 2008–09 में अमेरिका और यूरोप में आई मंदी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई राजकोषीय उपायों का उपयोग किया था। सरकारी खर्च बढ़ाया गया था और साथ ही साथ टैक्सों में भारी कटौती कर यह प्रयास किया था कि देश में मांग न घटने पाए और देश ऊंची ग्रोथ बनाए रखे।

भारत की अर्थव्यवस्था शेष दुनिया से कुछ इस कदर अलग है कि जबकि वर्ष 2008–09 में विकसित देशों की जीडीपी 2 से 3 प्रतिशत घट गई, भारत में जीडीपी की ग्रोथ 7 प्रतिशत के आसपास रही। वर्ष 2008–09 से प्रारंभ मंदी के दौरान अमेरिका, यूरोप और भारत की सरकारों के

पास खर्च बढ़ाने का विकल्प संभव था। अकेले अमेरिका में 1600 अरब डॉलर से भी ज्यादा के बचाव पैकेज दिए गए।

भारत सरकार ने भी एफआरबीएम एक्ट को ताक पर रखते हुए भारी बचाव पैकेजों का उपयोग किया। आज अर्थव्यवस्था में उठाव लाने के लिए इन सब की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ष 2011–12 के दौरान हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6 प्रतिशत तक पहुंचने के कारण खतरे का आगाज दे रहा है। ऐसे में सरकार का खर्च और बढ़ाना या टैक्सों में छूट व्यावहारिक विकल्प नहीं है।

कहा जा सकता है कि राजकोषीय विकल्प अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। पिछले लगभग दो वर्षों में तेरह बार ब्याज दरों को बढ़ाते हुए (एक बार ब्याज दरों में कटौती के अपवाद को छोड़कर) रिजर्व बैंक ने रेपोरेट को 8.25 प्रतिशत और रिवर्स रेपोरेट को 7.25 प्रतिशत तक बढ़ाकर देश में मांग बढ़ने की संभावनाओं को समाप्त करने का काम किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक हर माह जब अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करता है तो आर्थिक विश्लेषक हमेशा यह अपेक्षा लगाकर रखते हैं कि इस बार तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाने का काम करेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। 30 अक्टूबर को घोषित मौद्रिक नीति से भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले दो वर्षों से ब्याज दरों में लगातार वृद्धि के बावजूद महंगाई की दर थमने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन रिजर्व बैक की मृग मरीचिका का कोई अंत ही नहीं है।

हालांकि रिजर्व बैंक का तर्क सही है कि चूंकि महंगाई दर थमने का नाम नहीं ले रही तो ऐसे में ब्याज दरों में कटौती से महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। लेकिन यह भी सही है कि राजकोषीय उपायों के अभाव में देश में मांग को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है।

यदि सरकार अपना खर्च बढ़ाकर या करों में कमी करके मांग बढ़ाने का प्रयास करती हैं तो उससे दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो यह कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार पर कर्ज बढ़ेगा और सरकार की भविष्य के लिए ब्याज की देनदारियां और बढ़ जाएंगी।

दूसरा नुकसान यह होगा कि जीडीपी में धीमेपन के चलते मांग बढ़ने से महंगाई और भयंकर रूप धारण कर लेगी। अगर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को घटाने का काम किया जाता है तो उससे भी देश में मांग बढ़ाई जा सकती है।

आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र रुपये के अवमूल्यन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण ऊंची लागतों से त्रस्त है। ऊंची ब्याज दरों के कारण भी उसकी लागत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है।

वर्ष 2000 के बाद ब्याज दरों में कटौती होने के कारण देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग तो बढ़ी ही, निवेश की मांग में भी भारी वृद्धि हुई। उस दौरान सड़कें हों या अन्य प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर, सभी के विकास को बल मिला। कम ब्याज दरों के चलते ऑटोमोबाइल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के साथ–साथ मकानों की मांग में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था को मांग का समर्थन मिलने के साथ विकास जो दर पहले 5 प्रतिशत के आसपास चल रही थी, बढ़कर 7 प्रतिशत तक पहुंच गई। कीमतों में वृद्धि भी 3 से 4 प्रतिशत के आसपास रही।

आज उसी नीति को दोहराने की जरूरत है। ऊंची ब्याज दरों के चलते ऑटोमोबाइल और मकानों की मांग में ठहराव से निपटने का यह एक सार्थक विकल्प हो सकता है। यदि ब्याज दरों को घटाया जाएगा तो केवल घरों और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में ही वृद्धि नहीं होगी, बल्कि निवेशक भी नए निवेश की ओर आकृष्ट होंगे।

आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र रुपये के अवमूल्यन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण ऊंची लागतों से त्रस्त है। ऊंची ब्याज दरों के कारण भी उसकी लागत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ी लागत से राहत देना भी जरूरी है। ब्याज दरों को घटाकर उद्योगों की लागतों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ निवेश में आए धीमेपन को भी इससे दूर किया जा सकता है।

ब्याज दरें कम होंगी तो नए निवेश बढ़ेंगे। न केवल नए उद्योग खुलेंगे, बल्कि देश के सामने इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की चुनौती से भी निपटा जा सकेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पांच सालों में 50 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश का लक्ष्य है। ऊंची ब्याज दरों के चलते इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। इन तमाम कारणों से यह जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई के बावजूद हिम्मत जुटाकर ब्याज दरों में कटौती करे और देश में लगातार घटती ग्रोथ को थामने का काम करे।❑

अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार

पिछले आठ वर्षों में उस पर करों का इतना बोझ बढ़ा है कि अब वह इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आर्थिक सुधार की नीतियों का यही नतीजा है तो ऐसा विकास उसे नहीं चाहिए, जिसने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। देश की आर्थिक और सामाजिक दशा पर जब हम विचार करते हैं तो भारी निराशा होती है।

■ निरंकार सिंह

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बुनियादी ढांचे, निर्यात और राजकोषीय संतुलन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रियों को सलाह दी है कि इस पर अमल करके अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला।

देश की योजनाओं के अमल और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, तब तक किसी भी उपाय से देश की अर्थव्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता है।

सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और उसकी पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराने के बजाय तमाम मामलों की लीपापोती कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी महंगाई से त्रस्त है।

पिछले आठ वर्षों में उस पर करों का इतना बोझ बढ़ा है कि अब वह इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आर्थिक सुधार की नीतियों का यही नतीजा है तो ऐसा विकास उसे नहीं चाहिए, जिसने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। देश की आर्थिक और सामाजिक दशा पर जब हम विचार करते हैं तो भारी निराशा होती है।

सरकार जिस विकास दर (जीडीपी)का ढोल पीटती है, वह भी संदिग्ध है और उसका फायदा भी देश के कुछ अमीर घरानों को हुआ है। आम आदमी तो निराश, हताश और बदहाल है।

ऐसा लगता है कि हमारे तमाम राजनेता चर्चिल की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी राज चलाने के काबिल नहीं हैं। यदि उन्हें सत्ता मिली तो वे जनता का जीना मुश्किल कर देंगे।

आज देश में राजनीतिक दलों के बीच जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, वह जनसेवा के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय धन की लूटपाट का है। यही कारण है कि सरकार बदल जाने के बाद भी समस्याएं कम नहीं होती हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाने के साथ–साथ भ्रष्टाचार जिस

आज देश में राजनीतिक दलों के बीच जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, वह जनसेवा के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय धन की लूटपाट का है। यही कारण है कि सरकार बदल जाने के बाद भी समस्याएं कम नहीं होती हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाने के साथ–साथ भ्रष्टाचार जिस गति से बढ़ा है, उसकी मिसाल खोजनी मुश्किल है।

वास्तव में भारत का दुर्भाग्य, सभ्यता का दुर्भाग्य है। मौजूदा सभ्यता जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता या आधुनिक सभ्यता कहते हैं, उसके हिंसक और आत्मनाशी स्वभाव का परिचय दुनिया भर को हो रहा है। पश्चिम की समस्या के लिए उसकी सभ्यता ही जिम्मेदार हैं, जबकि हमारी समस्या अपनी सभ्यता को छोड़ने से पैदा हुई हैं।

गति से बढ़ा है, उसकी मिसाल खोजनी मुश्किल है।

भारत की आर्थिक व सामाजिक दशा के लिए हमारी आर्थिक सुधार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिन्हें बिना किसी तैयारी के लागू किया जा रहा है। विकास की यह अधिकांश वृद्धि अनौपचारिक एवं सेवा–क्षेत्रों से आती है और जिसके आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

सेवाओं के क्षेत्र में भी गत साल भर या उससे कुछ अधिक अवधि से आधिकारिक तौर पर मंदी में रहे हैं। सूचना तकनीकी में भयंकर प्रगति हुई। फिर वह ढह भी गई, केवल शिखर की तीन–चार कंपनियों को छोड़कर उन्हें भी बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी पूर्ववर्ती दशक के मुकाबले 2010 में नीची रही है और जनसंख्या वृद्धि की दर के साथ सामंजस्य रख पाने में असफल रही है। फिर भी हमने 5 करोड़ टन अनाज का विशाल भंडार जमा किया है और वह भी राजकीय कोष की विशाल कीमत पर।

केंद्र सरकार विशुद्ध सैद्धांतिक कारणों से गरीबों की सामर्थ्यानुसार कीमत पर अनाज के वितरण से इन्कार कर रही है, जबकि भारत में विश्व के सर्वाधिक कुपोषित बालकों व वयस्कों की जनसंख्या है।

सन 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की नई अर्थनीति पूर्णतः लागू की गई तो यह वादा किया गया था कि भारत 2001 तक गरीबी की दुःखद स्मृति को पीछे छोड़कर एक उन्नत आर्थिक वृद्धि की दर हासिल कर लेगा। लेकिन आज लगभग 22 वर्ष के बाद भी देश में गरीबी और भुखमरी की समस्या ज्यों की त्यों हैं, बल्कि कुछ बढ़ी ही है।

वास्तव में हमारे पास प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधन यदि समान रूप से वितरित हों तो संघर्ष की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वास्तव में भारत का दुर्भाग्य, सभ्यता का दुर्भाग्य है। मौजूदा सभ्यता जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता या आधुनिक सभ्यता कहते हैं, उसके हिंसक और आत्मनाशी स्वभाव का परिचय दुनिया भर को हो रहा है।

पश्चिम की समस्या के लिए उसकी सभ्यता ही जिम्मेदार हैं, जबकि हमारी समस्या अपनी सभ्यता को छोड़ने से पैदा हुई हैं। उसकी समस्या उसकी खुद की सभ्यता का विकास है, क्योंकि वह कुल मिलाकर हिंसा का ही विकास और विस्तार है, जबकि भारत की समस्या अपनी सभ्यता का क्षय और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के कारण बढ़ी है।

भारत अगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, इस शिकंजे से मुक्त नहीं हुआ तो विश्व को इस अंधकार युग से निकालने का रास्ता दिखा सके, ऐसी भी दूसरी संस्कृति बची नहीं है। ❑

सन 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की नई अर्थनीति पूर्णतः लागू की गई तो यह वादा किया गया था कि भारत 2001 तक गरीबी की दुःखद स्मृति को पीछे छोड़कर एक उन्नत आर्थिक वृद्धि की दर हासिल कर लेगा। लेकिन आज लगभग 22 वर्ष के बाद भी देश में गरीबी और भुखमरी की समस्या ज्यों की त्यों हैं, बल्कि कुछ बढ़ी ही है।

आम आदमी से दूर भागती सरकार

अर्जुन सेनगुप्ता समिति का मानना है कि देश की कुल आबादी का 38 प्रतिशत भाग गरीब है। इस सरकार के आठ साल के राज में कमरतोड़ महंगाई के कारण गरीबी और कुपोषण में और वृद्धि हुई है। एक ओर तो भ्रष्टाचार के कारण मुट्ठीभर लोग अल्पकाल में ही अरबपति बन रहे हैं तो दूसरी ओर नीतिगत अपंगता के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगतने को अभिशप्त है।

■ **बलवीर पुंज**

अपने मंत्रिमंडल को कथित तौर पर युवा और ऊर्जावान बनाने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नए मंत्रिमंडल से राष्ट्र निर्माण में जुट जाने की अपील की है। महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास सरकार पर घटा है। उसे दोबारा हासिल करने का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रनिर्माण के काम में आरोप भी लगते हैं तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इस सरकार पर घोटालों के आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए। मीडिया ने भी नहीं लगाए। ये आरोप संवैधानिक निकाय–नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने लगाए हैं और जांच में वे सही पाए जा रहे हैं।

जब सरकार का मुखिया ही एक संवैधानिक निकाय की अनदेखी करने की सलाह दे रहा हो तो स्वाभाविक तौर पर सरकार की कार्यशैली पर हर देशभक्त को चिंता होगी। कॉमनवेल्थ घोटाले में महीनों कारावास भुगत कर बाहर आए कलमाड़ी और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के ए राजा और कनीमोरी को हाल ही में संसद की विभिन्न स्थायी समितियों का सदस्य बनाया गया।

अब मंत्रिमंडल के फेरबदल में आइपीएल घोटाले के कारण जिस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था उसे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बना दिया गया और विकलांगों का धन गबन करने के आरोपी केंद्रीय मंत्री को पदोन्नत कर विदेश मंत्री बना दिया गया। एक ओर डॉ. सिंह के मंत्रिमंडल में ऐसे कर्मवीर शामिल हैं वहीं पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी जैसे ईमानदार व्यक्ति को महत्वपूर्ण मंत्रालय से वंचित किया गया। क्यों?

प्रधानमंत्री ने बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता व्यक्त की है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते सुस्त आर्थिक विकास दर और राजकोषीय घाटे को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता स्वाभाविक है, किंतु प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पिछले आठ साल से केंद्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का राज है। 2004–05 के आर्थिक सर्वेक्षण में

सरकार का मुखिया ही एक संवैधानिक निकाय की अनदेखी करने की सलाह दे रहा हो तो स्वाभाविक तौर पर सरकार की कार्यशैली पर हर देशभक्त को चिंता होगी। कॉमनवेल्थ घोटाले में महीनों कारावास भुगत कर बाहर आए कलमाड़ी और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के ए राजा और कनीमोरी को हाल ही में संसद की विभिन्न स्थायी समितियों का सदस्य बनाया गया।

लिखा था, 2004–05 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आशातीत रहा। 2003–04 में आर्थिक विकास की दर 8.5 प्रतिशत रही, जो 1975–76 व 1988–89 के अपवाद को छोड़कर अब तक की सर्वाधिक है।

उसी सर्वेक्षण में 2003–04 के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर 9.6 प्रतिशत, सर्विस सेक्टर में 9.1 प्रतिशत और उद्योग में 6.6 प्रतिशत विकास दर की स्वीकृति है। यह उपलब्धि भाजपानीत राजग सरकार की थी। विरासत में मिली समृद्ध अर्थव्यवस्था को पिछले आठ सालों में किसने खोखला किया? हाल ही में आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए जब प्रधानमंत्री को कड़े कदम उठाने पड़े तो स्वाभाविक तौर पर उनकी आलोचना भी हुई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि ये फैसले नहीं किए जाते तो देश में 1991 जैसे हालात हो जाते। इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है?

सन 1991 में भारत की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपनी अंतरराष्ट्रीय देनदारियों को पूरा करने के लिए अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा था। उस दौरान मनमोहन सिंह पीवी नरसिंह राव के काल में वित्तमंत्री थे। उन्होंने ही उदारीकरण की नीतियां अपना कर अर्थव्यवस्था को समाजवादी जकड़न से मुक्ति दिलाई थी, किंतु पिछले आठ सालों में प्रधानमंत्री के अंदर का अर्थशास्त्री खामोश क्यों रहा? लोकलुभावन नीतियों के लिए वह राजकोष क्यों लुटाते रहे? क्यों शीर्ष स्तर पर मची लूट को वह सहते रहे?

विडंबना यह है कि सरकार आर्थिक विकास के लिए आम आदमी को ही निचोड़ने की योजनाएं बना रही है। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सीमित करने से रसोई गैस के सिलेंडर करीब 900 रुपये में उपलब्ध होंगे। इसमें भी अभी 26 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिसे हिमाचल और गुजरात के चुनावों के कारण टाल दिया गया है।

दिल्ली में बिजली की दरों में भारी वृद्धि को लेकर जनता आक्रोश में है। लोगों को राहत देने की जगह दिल्ली की कांग्रेसी सरकार की सलाह यह है कि जो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकते उन्हें बिजली कनेक्शन कटवा लेना चाहिए। यह कैसी मानसिकता है?

दिल्ली में बिजली की दरों में भारी वृद्धि को लेकर जनता आक्रोश में है। लोगों को राहत देने की जगह दिल्ली की कांग्रेसी सरकार की सलाह यह है कि जो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकते उन्हें बिजली कनेक्शन कटवा लेना चाहिए। यह कैसी मानसिकता है?

कोयला घोटाले के लिए सरकार का तर्क है कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ती दरों पर कोयला आवंटित किया गया। फिर बिजली के दाम क्यों बढ़े?

जनवरी, 2011 में देश में बिजली उत्पादन कुल क्षमता से 30,000 मेगावाट कम था, क्योंकि कोयले की कमी के कारण बिजली प्लांट अपनी क्षमता से कम बिजली उत्पादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्थिति सुधारने का भरोसा दिलाया, किंतु अक्टूबर, 2012 तक और बुरा हाल हो गया। पावर प्लांट अपनी क्षमता से 65,000 मेगावाट कम बिजली उत्पादन की स्थिति में आ गए, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने जहां ज्यादा कोयला खनन की जरूरत नहीं समझी, वहीं जिन निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित हुए उन्होंने कोयला बेचकर मोटी कमाई की।

सरकार देश के खुदरा व्यापारियों की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए द्वार खोल चुकी है, किंतु इस बात की चिंता किसी को नहीं कि भारतीय उद्यमियों के पास 9 लाख करोड़ की नकदी होने के बावजूद वे भारत में निवेश करने को क्यों तैयार नहीं हैं? आज महंगाई दर करीब आठ प्रतिशत है। औद्योगिक और कृषि विकास दर तीन प्रतिशत से कम और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत रहने का अंदेशा है, जो बजटीय अनुमान 4.6 प्रतिशत से काफी अधिक है।

गरीबी आंकने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के आंकड़े भ्रामक हैं। योजना आयोग शहरी क्षेत्र में 32.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5 रुपये खर्च करने वाले को गरीब नहीं मानता।

उसके अनुसार 40.74 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रहे हैं। वहीं अर्जुन सेनगुप्ता समिति का मानना है कि देश की कुल आबादी का 38 प्रतिशत भाग गरीब है। इस सरकार के आठ साल के राज में कमरतोड़ महंगाई के कारण गरीबी और कुपोषण में और वृद्धि हुई है। एक ओर तो भ्रष्टाचार के कारण मुट्ठीभर लोग अल्पकाल में ही अरबपति बन रहे हैं तो दूसरी ओर नीतिगत अपंगता के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगतने को अभिशप्त है। ❑

तंत्र के चक्रव्यूह में नक्सलवाद

खुद गृह मंत्रालय मानता है कि नक्सलवाद के नाम पर हर साल 50 करोड़ रुपये की अघोषित उगाही होती है। यानी नक्सलवाद के जरिये जिन लोगों को जमीनी स्तर पर बदलाव का सपना दिखाया जा रहा है, वे अब भी माओ और लेनिन की विचारधारा से समानता आधारित समाज का सपना देख रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनका नेतृत्व अपने मकसद से भटक गया है।

■ उमेश चतुर्वेदी

नक्सलवाद क्या वाकई ऐसा चक्रव्यूह है, जिसमें न सिर्फ पूरी की पूरी व्यवस्था फंसकर रह गई है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक और नौकरशाही तंत्र की गडबड़ियों के चलते नई व्यवस्था बनाने का सपना देखने वाले नौजवान भी घिर गए हैं। इससे निकलने की राह न तो मौजूदा व्यवस्था को सूझ रही है और न ही उसके जरिए नई सुबह का सपना देखने वाले नौजवानों को। देश के एक तिहाई इलाके को ऑक्टोपस जैसी भुजाओं में घेर चुके नक्सलवाद पर बनाई अपनी फिल्म चक्रव्यूह में ऐसा ही दिखाने की कोशिश की है। एक हद तक उनकी सोच अपनी जगह पर सही भी है।

नक्सलवाद से जूझ रहे देश को इससे निकलने की राह अगर सूझ भी रही होती तो इसके लिए ऐसे कदम जरूर उठाए जाते, जिससे जिंदगी गुजारने की बुनियादी जरूरतों से महरूम देश के करीब 200 जिलों की आबादी को नई राह सूझ पाती। ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ एक ही तरफ हो रही है। फिल्म के खूंखार नक्सली राणा जैसे सैकड़ों राणा ऐसे भी हैं, जिनका एकमात्र मकसद नक्सलवाद के सिद्धांत में कैद रहकर खुद को जनरक्षक सिद्धांतवाद का पैरोकार बताकर मजलूमों के लिए काम कर रहे बौद्धिकों के बीच अपनी साख बचाए रखना और असलियत में उसी व्यवस्था के उपादानों को भोगते रहना है, जिसके विरोध की बुनियाद पर नक्सलवाद का जन्म तो हुआ है और वह पनप भी रहा है। शोषण और अन्याय की मौजूदा व्यवस्था का आधार

गरीबों और मजलूमों की उपेक्षा ही है।

संविधान समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की गारंटी देता है, लेकिन आज तक समानता पर आधारित समाज हम नहीं बना पाए हैं। हमें मान लेना चाहिए कि नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। यह गड़बड़ी ही है कि नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए चक्रव्यूह के किसी कबीर की तरह कोई पढ़ा–लिखा शख्स छत्तीसगढ़ से झारखंड और ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में घुस जाता है। वहां जाकर उसे

70 के दशक के शुरुआती दिनों में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें सिरफिरे लोग नहीं थे। बाद में नौजवानों ने माओ के क्रांति बंदूक की नली से निकलती है को ही अपना आप्त वाक्य बना लिया और खून बहाने लगे। नक्सल आंदोलन की आज सबसे बड़ी खामी यही है कि बंदूक थामने वाले हाथ ताकत का अहसास होते ही खुद को उसी तरह कमाई में झोक देते हैं. .

व्यस्था की खामियों का पता चलता है तो वह नक्सलवाद के खात्मे की बजाय उसमें ही रम जाना पसंद करता है। जब वह व्यवस्था के सहयोग से मोहंता जैसे उद्योगपति की शह पर उजड़ते आदिवासियों की तकलीफ देखता है तो अपना मकसद भूल जाता है। तब उसे पुलिस की गोलियों की परवाह नहीं रहती। वह खुद को होम कर देता है। चक्रव्यूह में कबीर भी खुद को ऐसे ही उत्सर्ग कर देता है।

सवाल यह है कि क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत दूसरे प्रबुद्ध विश्वविद्यालयों के भी होनहार छात्र वाकई पागल हैं, जो पढ़ते–पढ़ते अपनी जिंदगी का मकसद अबूझमाड़ के जंगलों के बीच आदिवासियों की दशा सुधारने और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ढूंढ़ने लगते हैं।

70 के दशक के शुरुआती दिनों में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें सिरफिरे लोग नहीं थे। बाद में नौजवानों ने माओ के क्रांति बंदूक की नली से निकलती है को ही अपना आप्त वाक्य बना लिया और खून बहाने लगे। नक्सल आंदोलन की आज सबसे बड़ी खामी यही है कि बंदूक थामने वाले हाथ ताकत का अहसास होते ही खुद को उसी तरह कमाई में झोक देते हैं, जैसे पुलिस या व्यवस्था का कोई दूसरा ताकतवर हरकारा कमजोर आदिवासियों और ग्रामीणों के खिलाफ अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है।

कुख्यात नक्सली नेता कामेश्वर बैठा कहने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे सांसद हैं, जो जेल में बंद हैं, लेकिन वे घोषित और ताकतवर नक्सली हैं। उनके बेटे पर आरोप है कि उसे लेवी दिए बिना झारखंड और ओडिशा के उन इलाकों में कोई ठेकेदार या उद्योगपति अपना धंधा नहीं चला पाएगा, जहां उसका असर है।

खुद गृह मंत्रालय मानता है कि नक्सलवाद के नाम पर हर साल 50 करोड़ रुपये की अघोषित उगाही होती है। यानी नक्सलवाद के जरिये जिन लोगों को जमीनी स्तर पर बदलाव का सपना दिखाया जा रहा है, वे अब भी माओ और लेनिन की विचारधारा से समानता आधारित समाज का सपना देख रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनका नेतृत्व अपने मकसद से भटक गया है।

उनके नेता अपने भौतिक–दैहिक सुख की भूख मिटाने में लगे हैं। यही कारण है कि जब आम जमीनी कार्यकर्ता को यह भूख मिटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है तो वह उसी पुलिस के सामने समर्पण करने से नहीं हिचकता है, जिसके खिलाफ वह हथियार थाम चुका होता है। अभी हाल ही एक फिल्म चक्रव्यूह में इसकी तरफ इशारा तो है, लेकिन गहराई नहीं। हालांकि हाल के दिनों में जैसी खबरें आई हैं, उनका सार भी इससे कुछ अलग नहीं है।

समानता के तमाम वैचारिक आधारों के बावजूद अगर नक्सलवाद को लेकर उन लोगों के नजरिये में यदि बदलाव आया है, जिन्हें अधिकार दिलाने की लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है, नक्सलियों द्वारा बेवजह बहाया गया खून।

पिछले साल जब नक्सलियों ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों की हत्या की तो आम लोगों के मन में भी नक्सलियों के प्रति गुस्सा भड़क उठा, आखिर जो पुलिसकर्मी मारे गए, उनमें से ज्यादातर उन्हीं आम लोगों के बीच से थे, जिनकी लड़ाई का दावा नक्सली करते रहे हैं।

वे पुलिसकर्मी व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के ताबेदार भर हैं। उनकी मौत से व्यवस्था का वह तबका नहीं हिलता, जो सचमुच देश की संपत्ति पर राज कर रहा है।

राजनीति और अर्थव्यस्था के ऊपरी पायदान का कॉकटेल निश्चित तौर पर इस समस्या को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अपनी व्यवस्था में आम आदमी को तरजीह न देने की जो फितरत घर कर गई है, वह इस समस्या को बढ़ावा ही देती है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के संविधान ने अपने हर नागरिक को उसका अधिकार और ताकत देने की जो संवैधानिक व्यवस्था लागू की है, वैसी व्यस्था और उसे लागू करने का इंतजाम हमारी व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए आम आदमी से जुड़े सवाल खास लोगों और खास व्यवस्था के सामने ताक पर रख दिए जाते हैं।

समस्या की शुरुआत दरअसल यहीं से होती है। इसीलिए आज आम आदमी और समाज के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित लोगों की आय का अंतर दस लाख गुना तक पहुंच गया है।

गांधीजी के रहते यह अंतर एक और चालीस का था। वे आम और खास की आमदनी के बीच की खाई को खत्म करना चहते थे।

उनका मानना था कि इस सोच के आधार पर ही भारत के गरीब नारायण तक के आंसू पोंछे जा सकते हैं, लेकिन गांधी हमारे लिए सिर्फ प्रतीक बन कर रह गए हैं? ऐसे प्रतीक जिनकी पूजा तो की जा सकती है, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नव आर्थिकी इसी प्रतीकवाद को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में नक्सलवाद ही क्यों, दूसरे कई तरह के चक्रव्यूह बने रहें तो हैरत नहीं होनी चाहिए। ❑

लेख

सर्वसमावेशी स्वदेशी

जोधपुर में दिनांक 8 जुलाई 2002 को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण के कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं . . . . **संपादक**

'स्वदेशी जागरण मंच' यह नाम सब लोग जानने लगे हैं। किन्तु इसका ग्रह योग कुछ ऐसा रहा कि इसके स्थापना के पूर्व से ही इसका विरोध होता रहा। मैं बंगाल में गया था, वहां भाषण में कहा था, कि हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं। प्रेस में भी वह भाषण छपा था, तुरंत कम्युनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे यह संघ वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है, इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने, कहा होगा कि तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो और इसके कारण विदेशी माल जब पूरा हट जाएगा, स्वदेशी मार्केट से, तो फिर हम लोगों का विदेशी कॉम्पीटीटर न होने के कारण उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का, अनाप–शनाप शोषण करना हमारे लिए संभव होगा, चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे, इसीलिए उद्योपतियों ने इनको पैसा दिया है।

इसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूरा होने तक काम करता रहेगा और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर वस्तु की लागत कीमत ''कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' उस पर लिखा जाना चाहिए।

हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु चाहे देशी

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी
10 नवम्बर 1920 – 14 अक्टूबर 2004

उद्योगपति की हो, विदेशी उद्योगपति की हो, उसकी 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने लागत कीमत' घोषित होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब घोषित होती है, उस पर लिखी रहती हैं, तो फिर अनाप–शनाप मुनाफा नहीं कमा सकते, हाँ कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहनी चाहिए यह तो सभी मानते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रीजनेबल होनी चाहिए। लेकिन आज जो होता है कि चार रुपए की चार सौ रुपए में बेची जाती है, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो यह हमने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद कम्युनिस्टों की तूती बंद हो गयी। उनको पता ही नहीं था, कि हमारे शास्त्र में कुछ है, उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं थे और इसीलिए वो निन्दा कर रहे थे, किन्तु उनका बोलना बन्द हो गया।

◆ ◆ ◆

आखिर स्वदेशी की अवधारण क्या है? वास्तव में यह मानना भूल है कि 'स्वदेशी' का संबंध केवल माल या सेवाओं से है। यह तो फौरी किस्म की सोच होगी। स्वदेशी का मतलब है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रबल भावना, राष्ट्र की रक्षा की भावना तथा समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वीकार। स्वदेशी की अवधारणा माने देशभक्ति का आविष्कार है, किन्तु इतना बोलने से प्रकट नहीं होता, राष्ट्रीय जीवन, व्यक्तिगत जीवन के सभी कार्यों में, स्वदेशी का दर्शन होना चाहिए।

◆ ◆ ◆

स्वदेशी क्या है? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि बात उस समय की है, जिस समय जापान, अमरीका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था, उस समय कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हुए 'ओरेन्जेस' तो अमरीका ने जापान को कहा, कि आपके यहां महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे आपकी मंडी में भेजेंगे, जापान ने कहा कि आपके संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अमरीका ने कहा कि नहीं हम भेजने ही वाले हैं, उस समय जापान को मानना पड़ा, जापान की मंडियां अमेरिकन संतरे से भर गई थीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी, एक भी संतरा नहीं बिका पूरे जापान में। जबकि जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसंद हैं फिर भी एक संतरा नहीं बिका इसी का नाम

स्वदेशी है।

◆ ◆ ◆

12 दिसम्बर को, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, पूरे देश में स्वदेशी दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया? तो उस उस दिन मुंबई के कपड़ा मिल के सामने जो विदेशी कपड़ा लेकर लॉरी आ रही थी, उसके सामने बाबूगेनू, इस नाम का एक सामान्य हमाल, वह लेट गया और उसने कहा कि ''मैं यह लॉरी नहीं जाने दूँगा'', ब्रिटिश सोल्जर उन्मत्त थे, उन्होंने ड्राइवर को कहा कि लॉरी इसके ऊपर चलाओ, लॉरी चलाई गई और उसकी मृत्यु हुई। यह जो उसका आत्म–बलिदान था, उसकी स्मृति में हर वर्ष 12 दिसंबर को हम स्वदेशी दिवस मनाते हैं, इससे स्वदेशी का कितना महत्व होगा, यह बात हमें समझनी चाहिए।

◆ ◆ ◆

चीन और कोरिया की सरकारों ने जब माईकल जैक्सन को इस बिना पर अपने देश में आने नहीं दिया कि उसका शो सांस्कृतिक हमला है, तब वे अपनी स्वदेशी भावना ही जाहिर कर रहे थे। यह घटना यह भी जताती है कि 'स्वदेशी' भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक आधार वाली विचारधारा है जो राष्ट्रीय जीवन के तमाम पहलुओं को खुद में समेटती है।

तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। ''देशप्रेम की साकार और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है स्वदेशी।'' देश प्रेम का अर्थ दुनिया से अलग–थलग रहना नहीं है, खासकर हमारी परंपरा में, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आधार पर टिकी है। इसके मुताबिक, मानवीय चेतना के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद का ही विस्तार है।

◆ ◆ ◆

यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के देशभक्त अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ नहीं हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का उनका आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध नहीं जाता है, बशर्ते उसका आधार समानता हो और उसमें हर देश के स्वाभिमान का सम्मान किया जाए। भूमंडलीकरण के पैरोकारों से उनका विरोध अलग और ज्यादा ठोस सवाल पर है।

◆ ◆ ◆

स्वदेशी वाले इस विचारको मानने के लिए तैयार नहीं है कि विकास का पश्चिमी मॉडल सार्वभौम है और दुनियाभर के लोगों को उसकी नकल करनी चाहिए। हालांकि वे सांस्कृतिक आदान–प्रदान को स्वीकारते हैं, मगर इस बात पर जोर देते हैं कि हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और हरदेश की प्रगति और विकास के मॉडल का उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तारतम्य होना चाहिए। आधुतिक बनने का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है। वे पश्चिम के हित में, विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय पहचानों को, गड्ड–मड्ड कर देने की कोशिशों का विरोध करते हैं।

आधुनिक पश्चिमी तकनीक और आर्थिक प्रणाली के साथ एक ऐसी सभ्यता आ रही है, जो गैर–पश्चिमी सभ्यताओं के अनुकूल नहीं है। विरोध का यह आधार है।

तो स्वदेशी, यह भावना है केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के विजयवाडा सेशन में जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम दिया था, उसमें प्रमुख बात रखी थी, कि नेशनल सेल्फ रिलाइंस, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, यह ठीक है कि एकदम सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती, कभी–कभी विदेशों से भी लेन–देन करनी पड़ेगी, लेकिन यह लेन–देन बराबरी के नाते होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमको डिक्टेट करें और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें ऐसा नहीं, बराबरी के नाते होना चाहिए। यह बात पंडित दीनदयाल जी ने कही थी।

◆ ◆ ◆

स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। लेकिन विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश की कृषि पर, हमारे देश के एक–एक उद्योग पर विदेशियों का कब्जा हो जाए। अब हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैण्डर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमरीका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ अमरीका के किसानों को जो पहली सब्सिडी मिलती थी, उससे चार गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और विकसनशील देशों को अमरीका कहता है तुम अपने यहां सब्सिडी कम करो और आखिर में सब समाप्त करो। अपने किसानों की वे सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कहा कि सब्सिडी खत्म करो?

◆ ◆ ◆

हमारा उद्देश्य है इस राष्ट्र का निर्माण करना, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवाद की कसौटी में राष्ट्र के उत्कर्ष की हमारी दृष्टि देश का सबसे छोटा आदमी जो सबसे गरीब, गयाबीता है, उसके उत्कर्ष को हम राष्ट्र का उत्कर्ष मानते हैं। राष्ट्र के उत्कर्ष की यही कसौटी है। ❑

(प्रस्तुति : विद्यानंद आचार्य)

पशुधन

गो दूध से लाभ

■ उमेश प्रसाद सिंह

हमारे पूर्वजों ने गोपालन, गाय की सेवा, सम्वर्धन गोदान आदि कार्य बहुत जांच पड़ताल के बाद किया था। दूध देने वाले और भी पशु हैं पर गाय का दूध अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं?

गाय की रीढ़ की हड्डी के अन्दर सूर्यकेतु नामक नाड़ी होती है। सूर्य की किरणे जब गाय के शरीर को छूती है तब सूर्यकेतु नाड़ी सूर्य की किरणों से स्वर्ण बनाती है। इसीकारण गाय के दूध और मक्खन में पीलापन होता है। इसमें विषनाशक तत्व पैदा होते है। सांप के काटने पर गाय के घी का सेवन करना चाहिए। इससे विष उतर जाता हे।

गोमूत्र में स्वर्णाश होने से इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय का गोबर से बीमारी फैलाने वाली जीवाणु पैदा नहीं होते। इसीलिए प्राचीनकाल से गाय के गोबर से घर लिपने की प्रथा प्रचलित हुई। हवन सामग्री में गाय का घी मिलाकर आहुति देने से आसपास का वातावरण काफी समय तक शुद्ध कीटाणु रहित व मनमोहक बना रहता है।

आज हमारे समाज और सरकार की अज्ञानता से देश में प्रतिदिन गोधन की हत्या की जा रही है। मानव जीवन में अनेक प्रकार का सहयोग करने के कारण ही गाय पूज्य है। गाय की रक्षा और पालन परिवार तथा समाज के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। जिस देश एवं राजधर्म में गोधन है, वास्तव में जीवन वहीं निवास करता है। हमारे देश की एकता की कड़ी को जोड़ने में गाय की बड़ी भूमिका है। अहिंसा की मूर्ति देवमयी गो की सेवा अपना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

प्रतिदिन गो दूध का सेवन करने वालो को कैंसर जैसे भयानक रोग नहीं होते। इसका कारण है शुद्ध सोना, जो गाय का दूध पीने वालों के शरीर में जाता है। शरीर के नस–नस में प्रवेश कर उसे पूर्णरूप से शुद्ध और पवित्र बना देता है। इससे तेज बुद्धि और शरीर का पर्याप्त विकास भी होता है। ❑

फिजूलखर्ची

क्या पेड़ में पैसे उगते हैं

■ गिरीश अवस्थी

देश के प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी तथा विदेशी पूंजी निवेश के विषय पर देश की जनता को सम्बोधित करते हुए अपने संदेश में यह कहा कि क्या पेड़ पर पैसे उगते हैं। हम जनता की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते है।

यह सुनने में तो अच्छा लगता है किन्तु प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन–आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। एक ओर योजना आयोग यह कहता है कि शहरों में गांव में रहने वाले लोगों के भरण–पोषण के लिए 32 रुपए व 20 रुपए पर्याप्त है। किंतु दूसरी ओर दिखाई पड़ता है कि यूपीपीए की तीसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपने निवास पर यूपीए के सहयोगी दलों को जो भोज दिया, इसमें प्रति व्यक्ति थाली के लिए 7721/ रुपए खर्च किए, क्या इतने पैसों के खर्च करने के लिए प्रधानमंत्री ने पेड़ पर उगे हुए पैसों का इंतजाम किया।

एक ओर प्रधानमंत्री फिजूलखर्ची से बचने के लिए नसीहते देते है और दूसरी ओर यूपीए के भोज में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह रिपोर्ट श्री सुभाष अग्रवाल ने आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक की। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इस भोज में 375 लोग उपस्थित हुए, जिन पर कुल खर्चा रुपए 28,95,503 आया। जिसमें रुपए 26,440 के फूलों की सजावट की गयी थी तथा 14,42,678 का टेंट लगाया गया और 11,34,296 की कैटरिंग हुई। क्या इस फिजूलखर्ची पर प्रधानमंत्री की नजर नहीं जाती। एक तरफ गांव के रहने वालों को दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री महोदय जश्न मनाने में देश की जनता का लाखों रुपए फिजूलखर्ची में फूँक रहे हैं।

इतना ही नहीं पूर्व राष्ट्रपति की विदेश यात्रा में 200/– करोड़ रुपए खर्च हुए। एक तरफ देश में बेरोजगारी की समस्या मुँह बाए खड़ी है। वही राजनेता जो कि जन–प्रतिनिधि भी कहे जाते है के वेतन–भत्तों में वारे–न्यारे किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने 31 मई 2012 को फिजूलखर्ची में कटौती करने, विदेशी दौरों में कटौती करने में आज के बारे में नसीहत दी थी। किंतु आज तक उसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ❑

रपट

विदेशी कंपनियां यहां मुनाफा कमाने के लिए आयेगी न कि यहां के लोगों को रोजगार और सस्ता सामान देगी

एफ.डी.आई. के आने से खुदरा व्यापारी, किसान एवं उपभोक्ता सभी को भविष्य में नुकसान होगा। अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत फिर आर्थिक रूप से गुलाम हो जायेगा। वालमार्ट कंपनी अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए भारत में 52 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश के राजनेता किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। — अरविन्द प्रसाद

जमशेदपुर, 24 अक्टूबर, 2012, स्वदेशी जागरणम मंच, पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में आज कांग्रेस की भ्रष्ट केन्द्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा, कृषि मंत्री शरद पवार, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, वालमार्ट, टेस्को, कैरिफोर, मैट्रो एवं टार्गेट के फोटो रावण के दस सिरों में लगाये गये थे।

जमशेदपुर पश्चिम के पूर्व विधायक श्री सरयू राय ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार ने 14 सितंबर 2012 को भारत में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। जिसके तहत देश में दुनिया की विशालकाय खुदरा व्यापार की कंपनियों के भारत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इन कंपनियों के यहां आने से देश के खुदरा व्यापार में लगे पांच करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। सरकार के अनुसार खुदरा व्यापार में एफडीआई के आने से किसान उपभोक्ता तथा बेरोजगारों को लाभ होगा।

केन्द्र सरकार का तर्क है कि एफडीआई आने से देश की हालत सुधरेगी एवं एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बिल्कुल ही तर्कहीन एवं निराधार है। विदेशी कंपनियां यहां मुनाफा कमाने के लिए आयेगी न कि यहां के लोगों को रोजगार और सस्ता सामान देगी।

स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वांचल के संघर्ष वाहिनी प्रमुख बंदेशंकर सिंह ने कहा कि विदेशी कंपनियां अपने मुनाफा का मात्र 25 प्रतिशत इस देश में खर्च करेगी तथा 75 प्रतिशत अपने देश ले जायेगी। वालमार्ट के दुनिया के 28 देशों में कुल 9826 स्टोर में कुल 21 लाख कर्मचारी काम करते हैं। अगर सरकारी दावे के अनुसार भारत में 40 लाख लोगों के रोजगार के लिए इन कंपनियों को 19 हजार से अधिक स्टोर खोलने पड़ेंगे।

इंग्लैंड में ए.सी. निल्सन के द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण में यह बात उभरकर आई कि खुदरा व्यापार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा होने पर उपभोक्ता 40 प्रतिशत अधिक कीमत पर सामान खरीदने के लिए मजबूर है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव विजय आनंद मूनका ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व एफडीआई की अनुमति दी गई थी परंतु एक भी कंपनी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नहीं आई।

जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने कहा कि आज जर्मनी दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों ने अपने यहां के खुदरा व्यापारियों को बचाने के लिए वालमार्ट को देश से बाहर निकाल दिया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक अरविन्द प्रसाद ने कहा कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के आने से खुदरा व्यापारी, किसान एवं उपभोक्ता सभी को भविष्य में नुकसान होगा।

अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत फिर आर्थिक रूप से गुलाम हो जायेगा। वालमार्ट कंपनी अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए भारत में 52 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश के राजनेता किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अतः अब समय आ गया है देश की जनता इस भ्रष्ट सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंके।

कार्यक्रम जिला संयोजक जे.के.एम. राजू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से टाटा वर्कस यूनियन के उपाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, अशोक गोयल, गौरवशंकर, डा. अनिल राय, सत्यनारायण मिश्रा, गुरजीत, रामेश्वर प्रसाद, राजकुमार साव, राजपति देवी, राकेश सिंह, अभिषेक बजाज, आर.सी. पाठक, संजीत प्रमाणिक, पारसनाथ दुबे, महावीर बाग, संजय मिश्रा, घनश्याम दास, मुकेश कुमार, शंकर जोशी, देव कुमार, बिजय सिंह, संजय मिश्रा, देवी प्रसाद, बिनोद ठाकुर, आशुतोष राय, मंजू ठाकुर, जयंत श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। ❑

किसान पंचायत (मेरठ)

ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला नाम वालमार्ट

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम अपने भाषण में कंपनियों के पक्ष में दलील देकर खुद को उनका दलाल साबित कर रहे हैं। आठ साल में प्रधानमंत्री घोटालों के चौक्के–छक्के लगा रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। अब प्रधानमंत्री ही कांग्रेस का विसर्जन करेंगे।

सितम्बर माह में रिटेल में एफडीआई के खिलाफ मेरठ में किसानों ने हुंकार भरी। स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कालेज कंकरखड़ा में आसपास के कई जिलों के किसानों ने एफडीआई के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने वालमार्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बदला रूप बताया।

उन्होंने कहा आठ साल में प्रधानमंत्री लगातार खुद और देश को कमजोर कर रहे हैं। जिन देशों के दम पर प्रधानमंत्री खुद को मजबूत कहते थे, अब वही उन्हें कमजोर बता रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो किसानों का पैसा खेल पर खर्च न करें। अगर वालमार्ट देश में अपना प्रोडक्ट लाएगी तो यहां के लड़के सेल्स ब्वाय और लड़कियां सेल्स गर्ल बनकर रह जाएंगी। इसके अतिरिक्त आज चीनी मिलों की जमीन को प्लाट काटकर बेचा जा रहा है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक ने कहा देश का दुर्भाग्य ही है बजट में किसानों के खेत की प्यास बुझाने के लिए सिंचाई के मद में बजट 1100 करोड़ रुपए और कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट 17 हजार करोड़ रुपए खेत खलिहान पर चोट नहीं तो और क्या है। मौजूदा केन्द्र सरकार के नुमाइंदे 60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफ कर किसानों पर अहसान जता रहे हैं जबकि ये सत्ताधीश प्रतिवर्ष 40 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज उद्यमियों का माफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान एकजुट होकर ऐसे सत्ताधीशों को सकब सिखाने के लिए संघर्ष करें तभी किसान का स्वाभिमान जीवित रह सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम अपने भाषण में कंपनियों के पक्ष में दलील देकर खुद को उनका दलाल साबित कर रहे हैं। आठ साल में प्रधानमंत्री घोटालों के चौक्के–छक्के लगा रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। अब प्रधानमंत्री ही कांग्रेस का विसर्जन करेंगे।

उन्होंने कहा अग्रेजी शासन में भी उतने किसानों ने आत्महत्या नहीं की, जितनी आजाद भारत में किसान कर चुके

हैं। जिस पार्टी के नेता ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया, अब उसी पार्टी के प्रधानमंत्री जय वालमार्ट बोल रहे हैं। कंपनियों के दलालों को उखाड़ फेंकना है। मनमोहन अब गांधीजी की इच्छानुसार कांग्रेस का विसर्जन करेंगे।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश प्रभारी डॉ. चंद्रमोहन ने कहा कि एफडीआई का आना देश के लिए बड़ा खतरा है। पहले ही चाइना मेड सामान के कारण हमारे लघु उद्योग संकट में है। एफडीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को चुनौती है। वहीं किसान और खेत खलिहान को इससे बड़ा खतरा है। किसानों के पास अब खुद का स्वाभिमान बचाने के लिए संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

एफडीआई का आना देश के लिए बड़ा खतरा है। पहले ही चाइना मेड सामान के कारण हमारे लघु उद्योग संकट में है। एफडीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को चुनौती है। वहीं किसान और खेत खलिहान को इससे बड़ा खतरा है।

– डॉ. चंद्रमोहन

स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने कहा कि देश में हर पांच मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। देश का अन्नदाता वर्तमान में दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज बना है।

पंचायत के संयोजक एवं पूर्व विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि अब किसान क्षमा याचना नहीं करेगा संघर्ष कर किसान विरोधी ताकतों को करारा जवाब देगा।

किसान पंचायत में मदनपाल उबड़िया, देवेन्द्र तोमर, डॉ. महक सिंह, रामपाल, विनोद चौधरी, राजेन्द्र सिंह, लाखन सिंह ने भी किसानों का दर्द बयां किया। ❑

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं आलू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खुली चर्चा – एक रपट

पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान जिले के सिब्ताई हाई स्कूल के मैदान में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन दिनांक 14 सितम्बर 2012 को किया गया। खुली चर्चा में लगभग 70 किसान एवं खुदरा व्यापारियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री धनपत अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट (अखिल भारतीय सह संयोजक) ने की। श्री प्रणय रॉय (संयोजक, पश्चिम बंगाल), श्री सुब्रत मंडल (आयोजक, पश्चिम बंगाल), श्री रथिन दास (सह संयोजक, पश्चिम बंगाल), श्री समीर बिस्वास (संयोजक, कोलकाता). श्री सुब्रत मण्डल सहित कई कार्यकर्त्ता चर्चा में शामिल हुए।

डॉ. धनपत अग्रवाल ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने और आपूर्त्ति श्रृंखला प्रबंधन से किसानों और छोटे किसानों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। श्री प्रणय राय ने इन विषयों पर स्वदेशी जागरण मंच के आंदोलन पर प्रकाश डाला और इस संबंध में भविष्य की योजनाओं की चर्चा की।

उन्होंने बताया कि आलू की न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में पश्चिम बंगाल से आंदोलन शुरू हुआ है और जल्द ही यह विभिन्न स्थानों पर आलू किसानों को संगठित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेगा।

खुली चर्चा में भाग लेने आए बर्द्धमान जिले के अन्य प्रमुख किसानों ने भी भाषण दिया। नवम्बर 2012 में एक प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं कृषि विपणन विभाग के मंत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जाएगा।

शाम चार बजे एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 40 गांव से आए लगभग 400 किसानों ने हिस्सा लिया। अत्यन्त ऊर्जा पूर्ण एवं स्पंदन से परिपूर्ण इस कार्यक्रम से किसानों के बीच एक उत्साह का संचार हुआ और आलू चासी किसानों के आंदोलन को एक नया बल मिला। कई नए किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े।

स्वदेशी जागरण मंच पश्चिम बंगाल ने इससे पूर्व हुगली वर्द्धमान, चौबीस परगना जिलों में पहले ही ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए थे और उन कार्यक्रमों में उपस्थित किसानों की भारी संख्या अत्यंत उत्साहवर्द्धक रही थी। ❑